



सांक्षिप्त समाचार

रात में महिला के घर में घुसना, कपड़े उठाना दुष्कर्म की कोशिश नही

नई दिल्ली। दुष्कर्म से जुड़े 26 साल पुराने एक मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने अहम टिप्पणी करते हुए कहा है कि केवल रात में किसी महिला के घर में प्रवेश करना और उसके कपड़े उठाना भारतीय दंड संहिता के तहत दुष्कर्म या दुष्कर्म के प्रयास का अपराध नहीं माना जा सकता। हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले में बदलाव करते हुए मामले को महिला की गरिमा भंग करने और आपराधिक बल के इस्तेमाल से संबंधित अपराध माना है। जस्टिस प्रदीप कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि दुष्कर्म किए जाने के पर्याप्त रूप से निकट कोई प्रत्यक्ष कृत्य भी, परिस्थितियों के आधार पर, भारतीय दंड संहिता के तहत दुष्कर्म के प्रयास का अपराध नहीं माना जा सकता। प्रत्यक्ष कृत्य से आशय अपराध की योजना को पूरा करने की दिशा में उठाए गए वास्तविक और ठोस कदम से है। यह फैसला 31 अगस्त को सुनाया गया था और सोमवार को सार्वजनिक किया गया। आरोपी ने जालशिला सत्र अदालत द्वारा 25 जुलाई, 2006 को सुनाई गई चार साल के सश्रम कारावास की सजा को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

डॉक्टरों से मारपीट करने वाले नेताओं को फौरन लें हिरासत में

नई दिल्ली। अस्पतालों में डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ पर बढ़ते हमलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बेहद कड़ा और तलख रख अपनाया है। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट आदेश देते हुए कहा कि डॉक्टरों के साथ मारपीट करने वाले राजनीतिक दलों के नेताओं और उनके समर्थकों को तुरंत हिरासत में लिया जाए। महाराष्ट्र में डॉक्टरों पर नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा किए जा रहे हमलों की हालिया घटनाओं पर गहरी चिंता जताते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि ऐसे तत्वों को किसी भी सूरत में खुलेआम घूमने की छूट नहीं दी जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह सख्त टिप्पणी कल्याण स्थित शास्त्रीनगर अस्पताल में डॉक्टरों पर हमले के मामले में जमानत की शर्तों को चुनौती देने वाली शिवसेना पार्षद रमेश सुक्रिया म्हात्रे की याचिका पर सुनवाई के दौरान की।

लुधियाना में 3 महीने की गर्भवती पत्नी की पीट-पीटकर हत्या की

लुधियाना। पंजाब में नशे के बढ़ते प्रभाव के बीच लुधियाना जिले के गांव बुर्ज लिट्टों से एक बेहद दर्दनाक मामला सामने आया है। यहां तीन महीने की गर्भवती 25 वर्षीय महिला हरप्रीत कौर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका के मायके वालों ने उसके पति जसप्रीत सिंह उर्फ जस्सा पर नशे की हालत में मारपीट कर उसकी हत्या करने का आरोप लगाया है। इस घटना में हरप्रीत के गर्भ में पल रहे अजन्मे बच्चे की भी मौत हो गई। पुलिस ने मृतका के परिजनों की शिकायत के आधार पर पति जसप्रीत सिंह और उसके दादा जोगिंदर सिंह को हिरासत में लिया है।

साय कैबिनेट की बैठक में हुए अहम फैसले

साय कैबिनेट में निर्यात प्रोत्साहन नीति 2026-30 को मंजूरी

■ एनएसटीआई के लिए नवा रायपुर में 10 एकड़ जमीन आवंटित रायपुर। संवाददाता

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में लिए गए निर्णयों के संबंध में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने जानकारी दी। मंत्रिपरिषद ने राज्य को देश के प्रमुख निर्यात केंद्र के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से 'छत्तीसगढ़ निर्यात प्रोत्साहन नीति 2026-30' को मंजूरी दी है। नई नीति के माध्यम से प्रदेश में मजबूत निर्यात इकोसिस्टम और लॉजिस्टिक्स

इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने, निर्यातकों को बेहतर बाजार पहुंच एवं व्यापार सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ ही कृषि एवं औद्योगिक क्षेत्रों में मूल्य सर्वाधिक उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा दिया जाएगा। इस नीति के तहत ई-कॉमर्स, व्यापार मेलों एवं प्रदर्शनियों के माध्यम से प्रदेश के उद्यमियों और निर्यातकों की अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक सीधी पहुंच बढ़ाई जाएगी। इस नीति का लक्ष्य छत्तीसगढ़ के निर्यात में गुणात्मक एवं मात्रात्मक वृद्धि के साथ प्रदेश को 'राष्ट्रीय एवं वैश्विक बाजारों से और मजबूती से जोड़ना है। मंत्रिपरिषद ने नवा रायपुर अटल नगर में नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (इस्सट्यू) की स्थापना के लिए एक और महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए भारत सरकार के कौशल विकास एवं उद्यमशीलता निदेशालय को ग्राम तेंदुवा में 10 एकड़ भूमि नि:शुल्क



आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत से विकसित होने वाले इस संस्थान में आधुनिक शैक्षणिक, प्रशासनिक एवं छात्रावास सुविधाएं विकसित की जाएंगी। यहां दीर्घकालिक पाठ्यक्रमों में प्रतिवर्ष 1,000 तथा अल्पकालीन कार्यक्रमों में 3,000 प्रशिक्षुओं को आज के उद्योगों की जरूरत के अनुरूप

संविदाकर्मियों-नगर सैनिकों को बड़ी राहत

मंत्रिपरिषद ने राज्य शासन के अधीन कार्यरत स्थायी/अस्थायी शासकीय सेवकों, निगम-मंडल एवं स्वाशासी संस्थाओं के कर्मचारियों, संविदाकर्मियों तथा नगर सैनिकों को अन्य शासकीय सेवाओं एवं उच्च पदों के लिए आवेदन करने में बड़ी राहत देते हुए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 38 वर्ष से बढ़ाकर 45 वर्ष करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस निर्णय से शासकीय एवं संबद्ध संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को उच्च पदों एवं अन्य सेवाओं में आगे बढ़ने के अधिक और समान अवसर प्राप्त होंगे। इस संबंध में राज्य शासन द्वारा एकीकृत स्थायी दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे। मंत्रिपरिषद ने दुर्ग जिला न्यायालय के नवीन भवन निर्माण के लिए ग्राम तितुरडीह में बीआईटी कॉलेज के समीप 4 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके लिए भिलाई इस्पात संयंत्र के नाम दर्ज उक्त भूमि के बदले ग्राम पाहंदा, तहसील पाटन में 5.024 हेक्टेयर शासकीय भूमि भिलाई इस्पात संयंत्र को दी जाएगी। दोनों भूखंडों का वर्तमान मूल्य लगभग समान है। इस निर्णय से दुर्ग में जिला न्यायालय के लिए आधुनिक एवं सुव्यवस्थित नवीन न्यायालय परिसर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त होगा और न्यायिक अधोसंरचना को और सुदृढ़ किया जा सकेगा।



बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन ने गिनाई उपलब्धियां सात अक्टूबर को जनसेवा के 25 साल पूरे करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी

नई दिल्ली/ एजेंसी

दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए 'सेवा संकल्प अभियान' पर चर्चा की। 7 अक्टूबर 2026 को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन-सेवा और समर्पण के 25 साल पूरे करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने कहा कि हम 25 करोड़ गरीब परिवारों को गरीबी से बाहर निकालने में सफल रहे हैं। यह पीएम मोदी के नेतृत्व और विजन का ही नतीजा था। उनका सपना, जो एक आम कार्यकर्ता के तौर पर शुरू हुआ और आज 'प्रधान सेवक' के रूप में देश को आगे



बढ़ाने तक पहुंचा है, पूरी तरह से उनके स्पष्ट विजन और पक्के संकल्प का ही परिणाम है। नितिन नबीन ने उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि आज, चाहे हम भव्य राम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, सोमनाथ या महाकाल कॉरिडोर की बात करें, हम कह सकते हैं कि उन्होंने देश की

सांस्कृतिक विरासत को पूरी तरह से नया रूप देने, उसे संरक्षित करने और विकसित करने की पहल की। अगर आज हम देश के युवाओं की बात करें, तो एक तरफ जहां देश के युवा कभी निराशा के माहौल में जी रहे थे, उन्हें उम्मीद और सकारात्मकता के माहौल में लाना वह काम है जो प्रधानमंत्री ने 2014 से किया है। सेवा संकल्प अभियान पर नितिन नबीन ने बताया कि अगले महीने के लिए 'सेवा संकल्प अभियान' की योजना बनाई गई है। 17 सितंबर 2026 से 17 अक्टूबर 2026 तक हम पूरे देश में यह महीने भर चलने वाला अभियान चलाएंगे।

वीडियो देखकर रह जाएंगे हैरान! खेत का गंदा पानी पीने को मजबूर हैं छात्र

जशपुर। एक और विकास के दावे हैं, दूसरी तरफयह तस्वीर. छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूल की बदहाल व्यवस्था को देखकर किसी का भी दिल पसीज जाएगा. बताया जा रहा है कि पिछले कई दिनों से स्कूल के पास बना हैंडपंप खराब पड़ा है, जिसके कारण स्कूली बच्चे खेतों से बहकर आ रहे पानी को पीने के लिए मजबूर हैं. दरअसल, पूरा मामला ग्राम पंचायत सुलेसा के शासकीय प्राथमिक शाला करमशाट का है. यहां पिछले कई दिनों से हैंडपंप से लाल पानी निकलता है. वहीं गांव में बिजली की समस्या के चलते बोर भी संचालित नहीं हो पा रहा है. ऐसे में छात्र-छात्राएं पास में खेतों से बहकर आ रहे पानी को पीने के लिए मजबूर हैं.

गणेश चतुर्थी के लिए शहर में तैयारियां जोर शोर से चल रही है.पंडालों के साथ साथ जगह जगह आकर्षक झांकियां बनाई जा रही है.इसी के साथ दुर्ग - भिलाई सहित राजधानी में सड़क किनारे गणेश प्रतिमाओं की स्टालें भी लगने लगी है.दुर्ग के सिविल लाइन स्थित समृद्धि बाजार में खैरामढ़, चिचोला और राजनांदगांव से आए कलाकारों ने भगवान गणेश की विभिन्न मुद्राओं और आकर्षक रूपों वाली प्रतिमाएं विक्री के लिए सजाई हैं। इन मनमोहक प्रतिमाओं को देखने के लिए राहगीर भी कुछ पल ठहरने को मजबूर हो रहे हैं। रंग-बिरंगी गणेश प्रतिमाओं से बाजार की रौनक देखते ही बन रही है। फोटो : नाहीद शेख

राजनाथ सिंह ने श्रीलंकाई राष्ट्रपति से की मुलाकात सुरक्षा-शांति का दोहराया संकल्प अंहम मुद्दों पर बनी विशेष सहमति

नईदिल्ली/ एजेंसी

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके से कोलंबो में मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत और श्रीलंका के बीच द्विपक्षीय संबंधों, रक्षा सहयोग तथा क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और समृद्धि से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। रक्षा मंत्री इस समय तीन दिवसीय दौरें श्रीलंका में हैं। राजनाथ सिंह ने मुलाकात के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके के साथ उनकी बातचीत बेहद उपयोगी और सार्थक रही। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र



मोदी की ओर से श्रीलंका के राष्ट्रपति को शुभकामनाएं दीं और उनकी सरकार के दो वर्ष सफ़लतापूर्वक पूरे होने पर उन्हें बधाई दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत और श्रीलंका सभ्यतागत रूप से जुड़े हुए देश, करीबी पड़ोसी और महत्वपूर्ण समुद्री साझेदार हैं। दोनों देशों ने एक

बार फिर इस बात की पुष्टि की कि वे अपने-अपने देशों के विकास और दोनों देशों की जनता के कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि भारत और श्रीलंका क्षेत्र में सुरक्षा, शांति और समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए भी मिलकर योगदान देते रहेंगे। दोनों देशों के बीच समुद्री सहयोग को भी विशेष महत्व दिया गया, क्योंकि हिंद महासागर क्षेत्र में भारत और श्रीलंका की भौगोलिक स्थिति उन्हें समुद्री सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण साझेदार बनाती है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार, 9 सितंबर को कोलंबो में हुई इस बैठक में दोनों नेताओं ने भारत और श्रीलंका के संबंधों को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई।

सागर में जहरीली शराब का कहर

28 मौतों का दावा,90 मरीज अस्पताल में भर्ती-पांच की हालत गंभीर

सागर/ एजेंसी

मध्य प्रदेश के सागर जिले में जहरीली शराब कांड के बाद हालात लगातार गंभीर बने हुए हैं। बंडा और आसपास के इलाकों से सामने आए इस मामले में अब तक 28 लोगों की मौत का दावा किया जा रहा है, जबकि प्रशासन की ओर से फिलहाल 15 मौतों की आधिकारिक पुष्टि की गई है। दूसरी ओर, बड़ी संख्या में मरीजों के अस्पताल भर्ती होने की संख्या को देखते हुए अस्पताल में विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं और स्थिति से निपटने के लिए स्वास्थ्य अमला लगातार निगरानी कर रहा है।

बीएमसी के आईसीयू में नौ गंभीर मरीज भर्ती बताए गए हैं। इनमें से पांच मरीजों की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है और उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है। डॉक्टर गंभीर रूप से प्रभावित मरीजों की लगातार निगरानी कर रहे हैं। बताया गया है कि कुछ मरीजों के शरीर से जहरीले तत्वों को बाहर निकालने के लिए बार-बार डायलिसिस की जरूरत पड़ रही है। इसके अलावा कई पीड़ितों की आंखों की रोशनी प्रभावित होने की भी जानकारी सामने आई है। जहरीले पदार्थ के असर से किडनी सहित अन्य अंगों पर भी गंभीर प्रभाव पड़ने की आशंका के बीच मरीजों का विशेष इलाज किया जा रहा है। इस घटना में मौतों का आंकड़ा बढ़ने की खबर लगातार सामने आ रही है। बीती रात इलाज के दौरान छापरी निवासी 38 वर्षीय अरविंद विश्वकर्मा



और धुरमार निवासी 32 वर्षीय रामस्वरूप अहिंवार की मौत की जानकारी सामने आई। इसके अलावा रिझावर सानौधा निवासी 50 वर्षीय नर्मदा प्रसाद की मौत की भी सूचना है। हालांकि अस्पताल प्रबंधन की ओर से इस मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट और

सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। स्वास्थ्य अधिकारियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती गंभीर रूप से प्रभावित मरीजों की स्थिति को स्थिर रखना है। जिन लोगों में आंखों की रोशनी और किडनी से जुड़ी समस्याएं सामने आई हैं, उनका विशेषज्ञों की निगरानी में इलाज किया जा रहा है। मामले के बाद प्रशासन ने जांच और कार्रवाई तेज कर दी है। आबकारी विभाग की तीन टीमों ने जिले में स्थित वेयरहाउस, डिस्ट्रिलरी और शराब दुकानों की गहन जांच की। जांच के दौरान फैक्ट्री, वेयरहाउस और सरकारी दुकानों में उपलब्ध 'सागर गोल्ड' ब्रांड को जांच में क्लीन चिट मिलने की जानकारी सामने आई है। वहीं बम्बइया और डीसीआर ब्रांड की सप्लाय पर अगले आदेश तक रोक जारी रखने का फैसला किया गया है।

दिल्ली से सीधे सागर के लिए रवाना हुए सीएम यादव

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मंगलावर को सागर पहुंचे, जहां हाल ही में हुए जहरीली शराब कांड में अब तक 32 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि करीब 150 लोग विभिन्न अस्पतालों में उपचाररत हैं। मुख्यमंत्री अपने दिल्ली प्रवास के बाद शाम 4:20 बजे सागर के लिए रवाना हो चुके हैं। सागर में वह शराब कांड की स्थिति की समीक्षा कर सकते हैं तथा प्रशासनिक अधिकारियों से राहत एवं उपचार व्यवस्थाओं की जानकारी लेंगे। सागर दौरे को शराब त्रासदी के मद्देनजर बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि घटना के बाद प्रदेशभर में आक्रोश का माहौल है और विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है।



सांसद निधि खर्च करने में भोजराज नाग सबसे पीछे

कांकेर लोकसभा में 16.46 करोड़ की निधि जारी, खर्च हुए महज 3.59 करोड़, 87 में सिर्फ 29 काम पूरे, 58 विकास कार्य अब भी अधूरे



बालोद। कांकेर लोकसभा क्षेत्र से सांसद भोजराज नाग के लिए सांसद निधि के खर्च और विकास कार्यों की प्रगति के आंकड़े चिंता बढ़ाने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के 11 लोकसभा सांसदों में सांसद निधि खर्च करने के मामले में जहां रायपुर सांसद बुजमोहन अग्रवाल और दुर्ग सांसद विजय बघेल सबसे आगे हैं, वहीं कांकेर सांसद भोजराज नाग सबसे पीछे नजर आ रहे हैं। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार कांकेर लोकसभा क्षेत्र में अब तक जारी सांसद निधि की महज 39.5 प्रतिशत राशि ही खर्च हो सकी है। सांसद निधि के तहत कांकेर लोकसभा क्षेत्र के लिए अब तक 16 करोड़ 46 लाख 72 हजार 734 रुपये जारी किए गए हैं। इसके मुकाबले महज 3 करोड़ 59 लाख 85 हजार 836 रुपये खर्च किए जा सके हैं। यानी क्षेत्र के विकास के लिए उपलब्ध कराई गई बड़ी राशि का पर्याप्त उपयोग अब तक नहीं हो पाया है।

87 कार्य स्वीकृत, 29 ही पूर्ण

सांसद भोजराज नाग की अनुशंसा पर अब तक 87 विकास कार्यों को स्वीकृत दी गई है। लेकिन स्वीकृत कार्यों की पूर्णता की स्थिति देखें तो तत्वीर और भी गंभीर नजर आती है। इनमें से सिर्फ 29 कार्य ही पूरे हो पाए हैं, जबकि 58 कार्य अब भी अधूरे हैं। यानी स्वीकृत कार्यों में करीब दो-तिहाई काम अभी पूर्णता की राह देख रहे हैं। सांसद निधि का उद्देश्य लोकसभा क्षेत्र में जनता की स्थानीय जरूरतों के अनुरूप विकास कार्यों को गति देना है। ऐसे में कार्यों की स्वीकृति के बाद उनके समय पर पूरा नहीं होने से उन क्षेत्रों के लोगों को विकास का अपेक्षित लाभ मिलने में देरी हो रही है।

प्रदेश में 2,284 कार्य स्वीकृत, 1,389 अधूरे

छत्तीसगढ़ के सभी 11 लोकसभा क्षेत्रों में सांसदों ने अब तक कुल 2284 विकास कार्यों को स्वीकृति दी है। इनमें वित्तीय वर्ष 2024-25, 2025-26 और 2026-27 के कार्य शामिल हैं। हालांकि इन कार्यों की पूर्णता दर बेहद धीमी है। अब तक महज 895 कार्य पूरे हुए हैं, जबकि 1 हजार 389 कार्य अभी अधूरे हैं। सांसद निधि के तहत प्रत्येक लोकसभा सांसद को प्रतिवर्ष 5 करोड़ रुपये मिलते हैं। यह राशि दो किस्मों में बांटी- द्वाई करोड़ रुपये के रूप में जारी की जाती है। पहली किस्म की लगभग 75 प्रतिशत राशि खर्च होने के बाद दूसरी किस्म जारी किए जाने का प्रावधान है। ऐसे में निधि के उपयोग की गति सीधे तौर पर नए विकास कार्यों की स्वीकृति और क्षेत्र में विकास की रफ्तार को प्रभावित करती है।

बस्तर, सगुजा और रायपुर में भी काम की रफ्तार सुस्त

सांसद निधि से स्वीकृत कार्यों के पूर्ण होने की स्थिति केवल कांकेर तक सीमित नहीं है। प्रदेश के कई लोकसभा क्षेत्रों में निर्माण कार्य अपेक्षित गति से पूरे नहीं हो रहे हैं। बस्तर में केवल 18.4 प्रतिशत, सगुजा में 21.2 प्रतिशत और रायपुर लोकसभा क्षेत्र में 23.2 प्रतिशत कार्य ही पूर्ण हुए हैं। हालांकि सांसद निधि खर्च के मामले में कांकेर सांसद भोजराज नाग की स्थिति प्रदेश के अन्य सांसदों की तुलना में सबसे पीछे बताई जा रही है। इससे क्षेत्र में स्वीकृत कार्यों की गिगारानी, क्रियान्वयन की गति और संबंद्धित एजेंसियों के बीच समन्वय को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं।

जनता के काम कब होंगे पूरे?-

कांकेर लोकसभा क्षेत्र आदिवासी और ग्रामीण बहुल इलाकों वाला क्षेत्र है, जहां सड़क, नाली, पेयजल, सामुदायिक भवन, शिक्षा और अन्य बुनियादी सुविधाओं से जुड़े छोटे-बड़े विकास कार्यों की लगातार जरूरत रहती है। ऐसे में सांसद निधि जैसी महत्वपूर्ण राशि का समय पर उपयोग नहीं होना सीधे तौर पर स्थानीय विकास को प्रभावित कर सकता है। अब सवाल यह है कि सांसद निधि से स्वीकृत 58 अधूरे कार्य अतिरिक्त कब तक पूरे होंगे और उपलब्ध निधि का पूरा उपयोग कब तक सुनिश्चित किया जाएगा? जनता की नजर अब सांसद भोजराज नाग और संबंद्धित कार्यदायी एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर टिकी है।

22 सितंबर से बसों का अनिश्चितकालीन महाबंद यातायात महासंघ ने रखीं 9 सूत्रीय मांगें



रोके जाएं, जैसे - उड़ीसा। सभी वाहनों में ऑनलाइन परमिट बनना चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष अनवर अली ने कहा कि यदि 22 सितंबर से पहले मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो प्रदेश भर के समस्त बस ऑपरेटर, मालिक, कर्मचारी एवं परिवहन व्यवसायी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। बेमेतरा जिला अध्यक्ष गोपाल साहू ने जिले के सभी बस संचालकों से महाबंद को सफल बनाने की अपील की है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में पूरी बसे बंद होगा जिसके लिए राज्य सरकार जिम्मेदार होगा, क्योंकि सरकार के आश्वासन के बाद ही 3/8/26 के एक दिवसीय प्रदर्शन को स्थगित किया गया था, हम बस वाले को डीजल ऑयल पाटर्न के साथ साथ सभी चीजों में वृद्धि हो गया है, सरकार के आश्वासन को पूरा एक माह से भी ज्यादा हो गया किंतु आज तक हमारी मांगो पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, इसलिए मजबूरन हमें हड़ताल का आह्वान करना पड़ा।

ढोलिया आंगन बाड़ी में मनाया

गया तीज मिलन समारोह



बेमेटरा। समीपस्थ ग्राम ढोलिया में अंगना में शिक्षा अंतर्गत तीज मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संस्था के द्वारा बच्चों की माताओं को विद्यालय में आमंत्रित किया गया, उन्हें

इस बात की जानकारी दी गई कि किस तरह खेल- खेल में बच्चों को पाठ्यक्रम की बातें सिखाई जाती हैं। संस्था की शिक्षिकाओं अर्चना झा,काजल दुबे एवं सुकन्या सिंह

राजपूत ने बच्चों की माताओं से शैक्षिक संवाद किया। साथ ही उन्हें बच्चों के साथ घर पर किस तरह का व्यवहार करें ताकि बच्चे शिक्षा को आनंद के साथ सीखने की प्रक्रिया में शामिल हो सकें। इस अवसर पर माताओं के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन भी रखा गया। जिसमें पुष्पा साहू को तीज क्रीन चुना गया। खेल की को प्रतियोगिता में रानी साहू एवं नृत्य में हिरदी साहू विजेता बनीं। भेजा यादव को ने श्रेष्ठ माता होने का गौरव हासिल किया। सभी माताओं ने इस तरह के अच्छे आयोजन के लिए संस्था का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर ग्राम की अभिभावक महिलाएँ एवं विद्यार्थी गण उपस्थित थे।

पाकेट मारने से से मना करने पर चाकू से किया वार पुलिस ने किया गिरफ्तार

बेमेटरा। गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी देते हुए धारदार वस्तु से किया वार, साजा पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया एक विधि के साथ संघर्षरत बालक भी शामिल है। प्रार्थी सुनीत साहू उम्र 41 वर्ष, निवासी मोहतरा थाना साजा जिला बेमेतरा द्वारा थाना साजा में रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि वह अपने साथी के साथ ग्राम मोहतरा से शासकीय शराब दुकान साजा शराब खरीदने आया था। शाम करीब 05:30 बजे शराब दुकान के सामने गेट के पास पहुंचने पर उसने देखा कि एक युवक एक अंजान व्यक्ति का पैकेट मार रहा था। प्रार्थी द्वारा उक्त युवक को ऐसा करने से मना करने पर आरोपी ने अश्लील गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी तथा अपने कमर से धारदार चाकू निकालकर प्रार्थी के दाहिने हाथ में कोहनी के पास वार कर दिया। इसी दौरान आरोपी के साथी भीम साहू ने भी गाली-गलौज करते हुए धारदार चाकू से प्रार्थी पर वार किया। प्रार्थी द्वारा वार को रोकने का प्रयास करने पर उसके दाहिने हाथ की बीच वाली उंगली में चोट लगी। घटना के दौरान एक व्यक्ति द्वारा बीच-बचाव किया गया। आसपास के लोगों को आते देखकर दोनों आरोपी शराब दुकान



के पीछे की दीवाल कूदकर मौके से फरार हो गए। प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना साजा में आरोपियों के विरुद्ध धारा 296, 351(3), 115(2), 3(5) बीएनएस एवं धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। उक्त घटना के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया। जिस पर पुलिस अधीक्षक त्रिलोक बंसल (भा.पु.से.)ने तत्काल आरोपी के विरुद्ध

आवश्यक कार्यवाही करने निर्देश दिए। जिसके तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. हरेश यादव एवं एसडीओपी बेरला श्रीमती रूचि वर्मा के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी साजा निरीक्षक जनक साहू को अपराध विवेचना हेतु थाना स्टाफ के साथ लगाया गया। प्रकरण में साजा पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया गया। विवेचना के दौरान आरोपी मनीष उर्फ भीम साहू को हिरासत में लेकर पुछताछ करने पर अपने एक अन्य साथी के साथ मिलकर अपना अपराध करना स्वीकार किया। प्रकरण में आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त धारदार वस्तु एवं अन्य साक्ष्य जप्त किया गया। प्रकरण में आरोपी मनीष उर्फ भीम साहू पिता पुरन साहू उम्र 19 वर्ष, निवासी भरतपुर वार्ड नंबर 03 साजा थाना साजा जिला बेमेतरा को न्यायिक रिमांड पर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। तथा एक विधि के साथ संघर्षरत बालक को माननीय किशोरा न्याय बोर्ड में पेश किया गया। इस संपूर्ण कार्रवाई में थाना प्रभारी साजा निरीक्षक जनक साहू, उम्र निरीक्षक असीम कर्तिनिया, प्रधान आरक्षक दुर्गेश तिवारी, शिवराज सिंह, आरक्षक अर्जुन धुवें, कैलाश पाटिल, राजू यादव, गोकुल सोनी, प्रमोद बंजारे सहित अन्य थाना स्टाफका महत्वपूर्ण भूमिका रही।

नलकूप ले गए सरपंच, बूंद-बूंद पानी को तरस रहे तेंदुआडीह के मासूम



कवर्धा। पंडरिया नगर से लगा हुआ ग्राम पंचायत सोनपुरी का आश्रित ग्राम तेंदुआडीह इन दिनों बुनियादी सुविधाओं की बदहाली का सामना कर रहा है। यहां प्राथमिक शाला में पढ़ने वाले मासूम बच्चों के लिए स्कूल परिसर में पेयजल की व्यवस्था तक नहीं है। शिक्षा सत्र शुरू होने के पहले से स्कूल परिसर में लगा नलकूप खराब पड़ा है। सुधार कराने के लिए सरपंच नलकूप को निकलवाकर ले गए, लेकिन उसे वापस लगाकर चालू नहीं कराया गया।

इसका खामीयाजा अब स्कूल के छात्र-छात्राओं और मध्यान्ह भोजन तैयार करने वाली रसोईया को भुगतना पड़ रहा है। स्कूल की शिक्षिका के अनुसार नलकूप खराब होने की जानकारी सरपंच को बार-बार दी जा चुकी है। इसके बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ। शिक्षा सत्र शुरू होने के बाद भी स्कूल परिसर में पेयजल व्यवस्था बहाल नहीं हो पाना पंचायत की कार्यप्रणाली और प्राथमिकताओं पर सवाल खड़े कर रहा है।

मरम्मत के नाम पर निकला नलकूप, स्कूल में पानी का संकट बरकरार

नलकूप खराब होने के बाद उसे सुधार कराने के लिए निकलवाया गया था। उम्मीद थी कि जल्द मरम्मत करकर वापस लगाया जाएगा और बच्चों को स्कूल परिसर में ही पानी उपलब्ध होगा। लेकिन समय बीतता गया और नलकूप वापस नहीं आया। नतीजा यह है कि स्कूल में रोजमर्रा की पानी की जरूरत बाहर से पूरी करनी पड़ रही है। छात्र-छात्राओं को पीने के पानी के लिए स्कूल परिसर के बाहर जाना पड़ रहा है। वहीं मध्यान्ह भोजन बनाने वाली रसोईया को भोजन तैयार करने, बर्तन साफकरने और अन्य जरूरी कार्यों के लिए भी बाहर से पानी लाना पड़ रहा है। प्राथमिक शाला में पढ़ने वाले छोटे बच्चों के सामने यह स्थिति किसी विडंबना से कम नहीं है।

पंचायत निधि के बावजूद बुनियादी सुविधा बरहाल

पंचायतों के पास मौलभूत सुविधाओं के विकास और रखरखाव के लिए विभिन्न मंदाें राशि उपलब्ध होती है। 15वें वित्त आयोग सहित पंचायत निधियों में पेयजल, स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य जन्यपयोगी कार्यों को प्राथमिकता दी जाती है। इससे बावजूद स्कूल का नलकूप लंबे समय से खराब पड़ा रहना पंचायत की प्राथमिकता और गिगारानी व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता है। बच्चों के लिए पेयजल कोई अतिरिक्त सुविधा नहीं, बल्कि स्कूल की अकिवार्य बुनियादी जरूरत है। इसके बावजूद यदि एक खराब नलकूप को समय पर दुरुस्त नहीं कराया जाता है तो पंचायत स्तर पर योजनाओं और उपलब्ध संसाधनों के उपयोग की प्रभावशीलता पर सवाल उठना स्वाभाविक है।

आग्रह के बाद भी सुधार नहीं

स्कूल की शिक्षिका द्वारा बार-बार जानकारी दिए जाने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं होने की बात सामने आई है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि शिकायत और समस्या समाधान के बीच पंचायत स्तर पर प्रभावी गिगारानी का अभाव बना हुआ है। स्कूल परिसर में पानी नहीं होने से बच्चों को बाहर जाना पड़ता है। छोटे बच्चों के लिए यह स्थिति असुविधा के साथ सुरक्षा का विषय भी है। शिक्षा व्यवस्था में बुनियादी सुविधाओं की अनदेखी का सीधा असर बच्चों के रोजमर्रा के स्कूल अनुभव पर पड़ता है।

अब नलकूप नहीं, जिम्मेदारी तय करने की जरूरत

मामले में संबंद्धित अधिकारियों को तत्काल संज्ञान लेकर तेंदुआडीह प्राथमिक शाला की पेयजल व्यवस्था बहाल कराने की जरूरत है। साथ ही नलकूप कब खराब हुआ, उसे सुधार के लिए कब निकाला गया और अब तक वापस क्यों नहीं लाया गया, इसकी स्थिति स्पष्ट की जानी चाहिए। तेंदुआडीह के मासूम बच्चों को पानी के लिए स्कूल परिसर से बाहर जाने की मजबूरी से तत्काल राहत मिलनी चाहिए। पंचायत निधि और 15वें वित्त आयोग जैसी व्यवस्थाओं का उद्देश्य ही गांवों में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करना है। ऐसे में स्कूल में पानी की व्यवस्था बहाल करना प्राथमिकता होनी चाहिए।

दल्लीराजहरा मॉडर्न आर्ट क्लब डी-मैक में शिक्षक दिवस का आयोजन



दल्लीराजहरा। दक्षीराजहरा मॉडर्न आर्ट क्लब डी-मैक में शिक्षक दिवस का आयोजन बड़े ही उत्साह, उमंग और अनीखे अंदाज में किया गया। कार्यक्रम में सम्मान, कला, मनोरंजन और सामाजिक संदेश का सुंदर संगम देखने को मिला। कार्यक्रम की शुरुआत महिलाओं द्वारा मानव श्रृंखला बनाकर अतिथियों एवं शिक्षिकाओं के स्वागत से हुई। तिलक लगाकर एवं पुष्प-वर्षा कर सभी का आत्मीय स्वागत किया गया। इसके पश्चात मां सरस्वती की वंदना और स्वागत गीत के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर विजय बोकर, मिलन एवं श्रीज्योती द्वारा सभी अतिथियों और शिक्षिकाओं को पुष्पगुच्छ भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान एक के बाद एक मनमोहक प्रस्तुतियों ने सभी का मन मोह लिया। कविता, गीत, एस्कल गायन, छत्तीसगढ़ी नृत्य, युगल

नृत्य और सामूहिक नृत्य की प्रस्तुतियों ने खूब तालियां बटोरीं। कार्यक्रम में विशेष रूप से कपिल शर्मा शो की तर्ज पर प्रस्तुत किया गया हास्य नाट्य कार्यक्रम आकर्षण का केंद्र रहा। तीन अलग-अलग किर्दारों के माध्यम से शिक्षकों की मजेदार नकल और हास्य प्रस्तुति ने दर्शकों को खूब मुग्धरुदाया। वहीं छत्तीसगढ़ी अंदाज में सरकार की केवाईसी से लेकर आधार कार्ड तक की मजेदार प्रस्तुति ने भी सभी को खूब हंसाया। इसमें कचरा बोदरा ने अपनी शानदार हास्य प्रस्तुति से कार्यक्रम में चार चांद लगा दिए। कार्यक्रम के अंत में फिर मिलेंगे चलते-चलते गीत पर डी-मैक के सभी सदस्यों ने सामूहिक नृत्य प्रस्तुत किया। इस शानदार प्रस्तुति ने पूरे वातावरण को उत्साह और उमंग से भर दिया तथा उपस्थित सभी लोग झुमने और नाचने पर मजबूर हो गए। डी-मैक परिवार हर वर्ष शिक्षक दिवस को केवल

एक औपचारिक कार्यक्रम के रूप में नहीं, बल्कि कला, मनोरंजन, आपसी प्रेम और समाज के प्रति सकारात्मक संदेश के साथ मनाने का प्रयास करता है। नाटक, हास्य प्रस्तुति, नृत्य, गीत, खेल एवं विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से हर वर्ष कुछ नया प्रस्तुत किया गया है। कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग एवं सहभागिता देने वाले सभी सदस्यों के प्रति डी-मैक परिवार ने हृदय से आभार व्यक्त किया। दामिनी, सत्य, सती, पूर्णमा, रावेंर, गायत्री, वीणा, मोनिका, किरण पांढरे, कांती भाभी, गुड्डिया भाभी, मालती, ज्योति, बेबी, मेघा, खुशबू, द्रोपदी, महक, किरण राजपूत, आशा, गीता, मंजू साहू, पूर्णिमा मंडल, रीता, वर्षा, वासु, हेम, ऐश्वर्या, रश्मि, अनू, स्मृति, श्यामली, सेवती, मंजू कथूरिया, पुष्पा, दीप्ति झा, तुषि, अनुराधा सिंह, निर्मला साहू, ममता वाहने, बबोता झा, मधुबिंलता, अंशु, माधुरी दुवे, रितु, रंजना गुलबर्के एवं किरण पटले आदि लोगों का सहयोग रहा। अंत में डी-मैक परिवार की ओर से सभी शिक्षकों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित की गईं।

मुख्यमंत्री गौरव अलंकरण शिक्षा दूत से सम्मानित हुए प्राथमिक विद्यालय दाढ़ी प्रधान पाठक



बेमेटरा। शिक्षक दिवस के पावन पर्व भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वे पल्लवी राधा कृष्णन का जन्म दिवस पर शिक्षक दिवस नवानगढ़ में मनाया गया जिसमें मंत्री दयाल दास बघेल खाद्य एवं नगरिक आभूषित एवं उपभोक्ता संरक्षण छत्तीसगढ़ शासन मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे एवं जनप्रतिनिधि शामिल हुए शिक्षा विभाग के सभी अधिकारी गण कर्मचारी शामिल हुए शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए शासकीय प्राथमिक विद्यालय दाढ़ी से चंद्रभान सिंह धुवें प्रधान पाठक को मुख्यमंत्री गौरव अलंकरण शिक्षा दूत से सम्मानित किया गया चंद्रभान सिंह धुवें ने अपने स्वयं वय से स्कूल को रंग रोहण कार्य करया गया बच्चों सिखाने के लिए श्रिच रचित वातावरण तैयार किया गया शिक्षा स्वच्छता अभियान के तहत स्वच्छ वातावरण तैयार किया गया बच्चों को

गतिविधियों के माध्यम से सिखाने के लिए कक्षा को सजाया गया जिसमें बच्चे सरल तरीके से सीखते थे चंद्रभान सिंह धुवें ने अपने स्वयं के वय पर संकुल सत्रीय दास बघेल खाद्य एवं नगरिक आभूषित एवं उपभोक्ता संरक्षण छत्तीसगढ़ शासन मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे एवं जनप्रतिनिधि शामिल हुए शिक्षा विभाग के सभी अधिकारी गण कर्मचारी शामिल हुए शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए शासकीय प्राथमिक विद्यालय दाढ़ी को जन सहयोग से 4 नग कैमरा सी सी टीवी प्राप्त हुआ नगर पंचायत दाढ़ी से वाटर कुलर प्राप्त हुआ 5 नग डरबिन 3नग दिवाल घड़ी जन सहयोग से प्राप्त हुआ चंद्रभान सिंह धुवें प्रधान पाठक ने इस उपलब्धि पर अपने स्टॉफके सभी कर्मचारी के सहयोग योदान के लिए बर्बाई शुभकामनाएं दी गईं।

250 की क्षमता, 420 बच्चों का बोझ, एकलव्य विद्यालय की व्यवस्थाओं पर सवाल



कवर्धा। तेरगांव जंगल स्थित पीएमश्री एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय की व्यवस्थाओं को लेकर पालकों ने जिला प्रशासन के सामने गंभीर शिकायत दर्ज कराई है। शिक्षा से लेकर छात्रावास, स्वास्थ्य, सुरक्षा और मूलभूत सुविधाओं तक अव्यवस्थाओं के आरोप लगाते हुए पालकों ने कलेक्टर से शिकायत की है। पालकों ने विद्यालय की पूरी व्यवस्था का निष्पक्ष स्थल निरीक्षण करारकर समस्याओं का तत्काल निराकरण करने की मांग की है। पालकों के अनुसार विद्यालय में पर्याप्त संख्या में शिक्षक होने के बावजूद विद्यार्थियों के शैक्षणिक स्तर में अपेक्षित सुधार नहीं हो रहा है। उन्होंने पिछले दो-तीन वर्षों में कक्षा 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणामों की निष्पक्ष समीक्षा कराने की मांग की है, ताकि विद्यालय की शैक्षणिक व्यवस्था की वास्तविक स्थिति सामने आ सके।

कृषि केन्द्रों का औचक निरीक्षण, बिना अनुमोदित स्रोत प्रमाण पत्र के कीटनाशक विक्रय पर प्रतिबंध

बेमेतरा। कृषि विभाग, विकासखंड साजा की टीम द्वारा नगर पंचायत देवकर में संचालित कृषि केन्द्रों का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कृषि आदातों की उपलब्धता, गुणवत्ता एवं वैधानिक दस्तावेजों की जांच की गई। निरीक्षण के दौरान श्रीजल कृषि केन्द्र एवं आहान कृषि केन्द्र, देवकर में कीटनाशकों के विक्रय हेतु अनुमोदित स्रोत प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं पाए जाने पर संबंधित कीटनाशकों के विक्रय पर प्रतिबंध लगाया गया। उक्त कार्रवाई कीटनाशी अधिनियम, 1968 एवं कीटनाशी नियम, 1971 के प्रावधानों के तहत की गई। इसी क्रम में चंद्राकर कृषि केन्द्र, देवकर के निरीक्षण के दौरान रासायनिक उर्वरकों की गुणवत्ता की जांच हेतु 04 उर्वरक नमूने लिए गए, जिन्हें नियमानुसार परीक्षण के लिए प्रयोगशाला प्रेषित किया गया है।



प्रयोगशाला से प्राप्त परीक्षण परिणाम के आधार पर नियमानुसार आगामी कार्रवाई की जाएगी। औचक निरीक्षण के दौरान दिनेश कुमार धुर्वे, कृषि विकास अधिकारी, विकासखंड साजा एवं विनय कुमार शर्मा, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, कार्यालय साजा उपस्थित रहे। कृषि विभाग के डिप्टी डायरेक्टर मोरध्वज डडसेना के द्वारा जिले में कृषि आदातों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने तथा किसानों को गुणवत्तापूर्ण कीटनाशक एवं उर्वरक उपलब्ध कराने के उद्देश्य से निरीक्षण एवं नमूना संकलन की कार्रवाई निरंतर जारी रखने की बात कही गई है।

डी-मैक में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई गई कृष्ण जन्माष्टमी



दल्लीराजहरा। दल्लैराजहरा मॉडर्न आर्ट क्लब (डी-मैक) द्वारा प्रतिवर्ष की परंपरा के अनुसार इस वर्ष भी कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व श्रद्धा, उत्साह एवं हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में भगवान श्रीकृष्ण की पूजा-अर्चना एवं आरती के साथ चित्रकला, मटकी फोड़ तथा राधा-कृष्ण वेशभूषा प्रतियोगिता सहित विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बच्चों के लिए भगवान श्रीकृष्ण के छायाचित्र बनाने की चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की गई। बच्चों ने अपनी

कल्पनाशीलता का परिचय देते हुए पेंटिंग, स्केचिंग, ऑयल पेस्टल एवं पेसिल कलर के माध्यम से भगवान श्रीकृष्ण के सुंदर चित्र बनाए। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले ज्योतिका टंडिया, ज्योतिका, रेखांस, सान्वी, लावण्या एवं सारण्या सहित सभी प्रतिभागी बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित एवं प्रोत्साहित किया गया। चित्रकला प्रतियोगिता का निर्णयन केशव पटेल द्वारा किया गया, जिन्होंने विश्वविद्यालय स्तर पर चित्रकला का प्रशिक्षण प्राप्त किया है। उनके द्वारा बच्चों को पुरस्कार वितरित किए गए।

पारंपरिक पोला एवं तीज मिलन कार्यक्रम का उत्साहपूर्वक हुआ आयोजन

दल्लीराजहरा। छत्तीसगढ़ की समृद्ध संस्कृति एवं परंपराओं को जीवंत बनाए रखने के उद्देश्य से रेलवे कॉलोनी की महिलाओं द्वारा पारंपरिक पोला एवं तीज मिलन कार्यक्रम का उत्साहपूर्वक एवं हर्षोल्लास के साथ आयोजन रेलवे इंस्टीट्यूट दल्लैराजहरा में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विधिवत पूजा-अर्चना के साथ किया गया। कार्यक्रम का सफल एवं आकर्षक संचालन दीप्ति राकेश कोझा द्वारा किया गया। इस अवसर पर महिलाओं के मनोरंजन हेतु विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताओं एवं गीत-संगीत, रैप वॉक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें सभी महिलाओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और कार्यक्रम का भरपूर आनंद उठया। कार्यक्रम के दौरान सेंट थॉमस इंग्लिश मीडियम स्कूल की शिक्षिकाएं प्रिया साहू एवं भारती साहू का रेलवे महिलाओं द्वारा सम्मान किया गया। इस सम्मान समारोह ने कार्यक्रम को और भी विशेष एवं यादगार बना दिया। कार्यक्रम के लिए रेलवे महिलाएं खेहा कुमारी,पूनम सहारे, भारती साहू, पी. प्रमिला मुरली, दीप्ति कोझा,



ऊषा कुमारी, पुष्पा टंडन, सुनीता कुशवाहा, पार्वती चंद्रवंशी, गोपिका कोसमा, प्रिया साहू, खुशबू कौशिक, सी एच त्रिवेणी, कृष्णा हरिप्रिय, मंजू साहू सभी का भरपूर सहयोग रहा। इस अवसर पर वार्ड क्रमांक 26 की

पार्षद टी. ज्योति ने रेलवे महिला मंडल एवं आयोजन समिति की सभी महिलाओं को पोला एवं तीज मिलन कार्यक्रम के सफल आयोजन पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। पार्षद टी. ज्योति ने कहा कि पोला और तीज जैसे पारंपरिक पर्व हमारी छत्तीसगढ़ी संस्कृति, परंपरा एवं सामाजिक एकता के प्रतीक हैं। ऐसे आयोजन महिलाओं को एक-दूसरे से जोड़ने के साथ-साथ हमारी संस्कृति और परंपराओं को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। उन्होंने रेलवे महिलाओं द्वारा किए गए इस सुंदर एवं सराहनीय आयोजन की प्रशंसा करते हुए भविष्य में भी इसी प्रकार सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने के लिए शुभकामनाएं दीं। टी. ज्योति पार्षद ने सभी रेलवे महिलाओं एवं क्षेत्रवासियों को पोला एवं तीज पर्व की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित कीं।

दल्लैराजहरा में बैंक ऑफ बड़ौदा की नई शाखा का उद्घाटन



ग्रामीण और अर्ध-शहरी विकास की दिशा में एक सशक्त पहल

बालोद। ग्रामीण और अर्ध-शहरी छत्तीसगढ़ में वित्तीय समावेश को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठते हुए, सर्वजनिक क्षेत्र के दूसरे सबसे बड़े बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा ने धमतरी क्षेत्र के दल्लैराजहरा में अपनी 62वीं शाखा का उद्घाटन किया। इस नई शाखा को दल्लैराजहरा और आसपास के गांवों के निवासियों को सुलभ और आधुनिक बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। शाखा का औपचारिक उद्घाटन बालोद जिले के पुलिस अधीक्षक किरण गंगाराम चव्हाण ने किया। इस अवसर पर रायपुर अंचल के अंचल प्रमुख दिवाकर पी. सिंह, धमतरी क्षेत्र के क्षेत्रीय प्रबंधक बानाम्बर बेहेरा और उप-क्षेत्रीय प्रबंधक अमित सिंह पटेल के साथ-साथ बैंक ऑफ बड़ौदा के अधिकारी और कई निवासी/व्यवसायी, स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) के सदस्य तथा स्थानीय ग्रामीण उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत मेहमानों के पारंपरिक स्वागत के साथ हुई, जिसके बाद धमतरी क्षेत्र के क्षेत्रीय प्रबंधक बानाम्बर बेहेरा ने स्वागत भाषण दिया।

ने किया। इस अवसर पर रायपुर अंचल के अंचल प्रमुख दिवाकर पी. सिंह, धमतरी क्षेत्र के क्षेत्रीय प्रबंधक बानाम्बर बेहेरा और उप-क्षेत्रीय प्रबंधक अमित सिंह पटेल के साथ-साथ बैंक ऑफ बड़ौदा के अधिकारी और कई निवासी/व्यवसायी, स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) के सदस्य तथा स्थानीय ग्रामीण उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत मेहमानों के पारंपरिक स्वागत के साथ हुई, जिसके बाद धमतरी क्षेत्र के क्षेत्रीय प्रबंधक बानाम्बर बेहेरा ने स्वागत भाषण दिया।

फाइनैशियल और साइबर फ्राड के मामलों के प्रति सतर्क रहने की दी सलाह

रायपुर अंचल के अंचल प्रमुख दिवाकर पी. सिंह ने अपने संबोधन में बताया कि नई शाखा खुलने से अब स्थानीय नागरिकों, व्यापारियों और ग्रामीणों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करना, सरकारी योजनाओं का लाभ उठाना और ऋण सुविधाओं तक पहुंच आसान हो जाएगी। उन्होंने बैंक के उपायों जैसे केंद्र सरकार के साथ सैलरी पैकेज, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के साथ सैलरी पैकेज (एसओए), छत्तीसगढ़ पुलिस सैलरी पैकेज आदि के बारे में भी जानकारी दी। पुलिस अधीक्षक किरण गंगाराम चव्हाण ने निवासियों से अपने परिवार के सभी सदस्यों के बैंक खाते खुलवाने का आग्रह किया ताकि वे औपचारिक वित्तीय प्रणाली से जुड़कर देश की अर्थव्यवस्था में योगदान दे सकें। उन्होंने बांच के सुचारू कामकाज और विकास के लिए पूरा प्रशासनिक सहयोग देने का प्रारोसा भी दिलाया। साथ ही, उन्होंने लोगों को बढ़ते हुए फाइनैशियल और साइबर फ्रॉड के मामलों के प्रति सतर्क रहने की सलाह दी और किसी भी तरह का फ्रॉड होने पर तुरंत नेशनल हेल्पलाइन नंबर 1930 पर संपर्क करने की अपील की, ताकि नुकसान को कम किया जा सके और समय पर कार्रवाई हो सके। कार्यक्रम के आखिर में, उप क्षेत्रीय प्रमुख अमित सिंह पटेल ने वहां मौजूद सभी गणमान्य व्यक्तियों और नागरिकों का आभार व्यक्त किया और समाज के हर वर्ग को प्रभावी और बिना रुकावट वाली बैंकिंग सेवाएं देने के अपने संकल्प को दोहराया। यह उद्घाटन इस क्षेत्र में फाइनैशियल पहुंच और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर विधिक जागरूकता शिविरों का आयोजन



बेमेतरा। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर लक्ष्मण प्रसाद वैद्य शासकीय कन्या महाविद्यालय, बेमेतरा में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में छात्राओं को संबोधित करते हुए बताया गया कि साक्षरता प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का महत्वपूर्ण आधार है। शिक्षा एवं साक्षरता के माध्यम से व्यक्ति अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों को समझने में सक्षम होता है तथा समाज में सम्मानपूर्वक एवं आत्मनिर्भर जीवन जी सकता है। अशिक्षा के कारण व्यक्ति अपने अधिकारों की जानकारी से वंचित रह जाता है और अनेक कार्यों के लिए दूसरों पर निर्भर हो जाता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का साक्षर होना आवश्यक है। इस अवसर पर सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण

द्वारा छात्राओं को निःशुल्क विधिक सहायता एवं विधिक सेवाओं के संबंध में जानकारी दी गई। साथ ही राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों की जानकारी प्रदान की गई। छात्राओं को नालसा के टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 15100 के संबंध में बताते हुए कहा गया कि जरूरतमंद व्यक्ति इस नंबर के माध्यम से निःशुल्क विधिक सहायता एवं कानूनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। शिविर के दौरान प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने की प्रक्रिया एवं पॉइंट व्यक्ति के अधिकारों के संबंध में भी जानकारी दी गई। साथ ही टोनेही प्रताड़ना अधिनियम के प्रावधानों तथा अंधविश्वास एवं टोनेही के नाम पर महिलाओं के साथ होने वाली प्रताड़ना के विरुद्ध उपलब्ध कानूनी संरक्षण के

संबंध में छात्राओं को जागरूक किया गया। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारी मित्रों द्वारा जिले के विभिन्न विद्यालयों में भी विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इनमें शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बेहेरा, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला, भूगवाय, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, उगरिया, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला, तिलका पारा नवगढ़ तथा तालुका साजा अंतर्गत शासकीय हाई स्कूल, परसबोड़ शामिल हैं। इन शिविरों के माध्यम से विद्यार्थियों को साक्षरता के महत्व के साथ-साथ उनके कानूनी अधिकारों एवं उपलब्ध निःशुल्क विधिक सेवाओं के प्रति जागरूक किया गया।

पीएमश्री सेजेस में आरओ वाटर कूलर की सौगात नगर पालिका अध्यक्ष ने किया विधिवत शुभारंभ



डोंगरगांव नगर। पीएमश्री स्वामी आत्मानंद स्कूल में मुख्य अतिथि नगर पालिका अध्यक्ष अंजु त्रिपाठी ने अपनी निधि से स्वीकृत वॉटर फिल्टर व आरओ का विधिवत शुभारंभ किया। उल्लेखनीय है कि पूर्व में स्कूल के विद्यार्थियों एवं शिक्षकों द्वारा विद्यालय में वॉटर फिल्टर एवं आरओ की मांग की गई थी। अध्यक्ष ने शिक्षकों व

विद्यार्थियों की मांग को प्राथमिकता देते हुए अपनी अध्यक्ष निधि से वॉटर फिल्टर व आरओ की स्वीकृति प्रदान की। शुभारंभ मौके पर प्रबंधन समिति अध्यक्ष सतीश कुमार पाण्डेय, एल्डरमेन गुलशन हिरवानी, आकाश त्रिपाठी, प्राचार्य बापल देवांगन, गणवीर तथा समस्त शिक्षक व शिक्षिकाओं सहित विद्यार्थीगण उपस्थित थे।

बेमेतरा जिला अस्पताल में साप्ताहिक टाइप-1 डायबिटीज क्लीनिक का शुभारंभ



बेमेतरा। जिला अस्पताल बेमेतरा में बच्चों में होने वाले टाइप-1 डायबिटीज के बेहतर प्रबंधन एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं के उद्देश्य से साप्ताहिक टाइप-1 डायबिटीज क्लीनिक का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर, डॉ बी एल राज जिला स्वास्थ्य अधिकारी, डॉ लोकेश साहू सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, डॉ नीतेश चौबे शिशु रोग विशेषज्ञ, डॉ ऋषभ शर्मा नोडल

अधिकारी आरबीएसके, राहुल RNMCH+ सलाहकार, डॉ स्वाति यदु अस्पताल प्रबंधक, आरती दत्ता मेट्टन एमसीएच, नर्सिंग ऑफिसर, एनसीडी नोडल अधिकारी, स्टाफ नर्स एवं काउंसलर गोविंद सिंह उपस्थित रहे।। इस क्लीनिक के माध्यम से टाइप-1 डायबिटीज से प्रभावित बच्चों को नियमित चिकित्सकीय परामर्श, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, काउंसलिंग एवं निःशुल्क इंसुलिन उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही बच्चों एवं उनके अभिभावकों को मधुमेह के

बेहतर प्रबंधन एवं नियमित फॉलो-अप हेतु आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा। WJCF के तकनीकी सहयोग से यह क्लीनिक प्रत्येक बुधवार को नियमित रूप से संचालित किया जाएगा, जिससे बेमेतरा जिले के टाइप-1 डायबिटीज से प्रभावित बच्चों को उनके निकट ही निरंतर एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी।

संपादकीय

केंद्र सरकार ने पंजाब तथा हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में अश्वनी कुमार मिश्रा का नाम अधिसूचित किया था। मगर पंजाब सरकार ने यह आरोप लगाया कि केंद्र ने यह कदम राज्य सरकार की राय का इंतजार किए बिना संवैधानिक नियमों तथा तय प्रक्रियाओं को दरकिनार करके उठाया। देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक दलों के बीच अलग-अलग मसलों पर

खींचतान एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। असहमति और आलोचना लोकतंत्र की बुनियाद की और ज्यादा मजबूत ही करती है। मगर सभी पक्षों की यह कोशिश होनी चाहिए कि इस दृढ़ की छाया कम से कम न्यायपालिका पर नहीं पड़े।विडंबना यह है कि कई बार न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर भी ऐसे टकराव सामने आते हैं, जिससे किसी खास मामले में इससे संबंधित पूरी प्रक्रिया कठघरे में खड़ी होती

है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने पंजाब तथा हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में अश्वनी कुमार मिश्रा का नाम अधिसूचित किया था। मगर पंजाब सरकार ने यह आरोप लगाया कि केंद्र ने यह कदम राज्य सरकार की राय का इंतजार किए बिना संवैधानिक नियमों तथा तय प्रक्रियाओं को दरकिनार करके उठाया।इस मसले पर अब केंद्र और पंजाब सरकार आमने-सामने हैं। टकराव की

तीव्रता का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि रविवार को पंजाब मंत्रिमंडल ने इस नियुक्ति को अधिसूचित करने के केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ एक प्रस्ताव भी पारित किया।जाहिर है, इस मसले पर अब यह विवाद खड़ा हो गया है कि क्या इसमें प्रक्रिया संबंधी कोई अनदेखी हुई है। हालांकि केंद्र का यह कहना है कि राज्य सरकार की राय लेना जरूरी है, लेकिन वह बाध्यकारी नहीं है।

इसके बाद पंजाब सरकार के विरोध को दरकिनार करते हुए न्यायाधीश अश्वनी कुमार मिश्रा को उनके नए पद पर शपथ दिला दी गई, मगर एक बार फिर न्यायाधीशों की नियुक्ति में केंद्र और राज्य की शक्तियों को लेकर जिस तरह के सवाल खड़े हुए हैं, उन पर स्पष्टता की जरूरत है।आखिर क्या वजह है कि जहां किसी मामले में केंद्र और राज्य की सहभागिता एक लोकतांत्रिक तकाजा है, वहां कई बार

खासतौर पर उन राज्यों की सरकारें खुद को उपेक्षित महसूस करती हैं, जहां विपक्षी दल सत्ता में होते हैं। न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया में अगर राज्य की कोई भूमिका है, तो उसे महत्त्व देना लोकतंत्र को मजबूती ही देगा। यों भी, इस संबंध में कोई फैसला करते हुए क्या यह ध्यान रखने की जरूरत नहीं है कि किसी राज्य की ओर से संवैधानिक अधिकारों को दबाने का आरोप न लगे या कोई अप्रिय विवाद न खड़ा हो !

यहां भ्रष्टाचार की बात करते समय एक सावधानी भी जरूरी है। किसी अधिकारी या व्यवसायी को बिना जांच दोषी ठहराना उचित नहीं। लेकिन यदि जांच में यह सिद्ध होता है कि नियमों के विरुद्ध निर्माण को जानबूझकर नजरअंदाज किया गया, निरीक्षण में लापरवाही हुई या किसी प्रकार की मिलीभगत रही, तो जिम्मेदारी केवल भवन मालिक तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। जिसने नियम तोड़े और जिसने नियम तोड़ने दिए-दोनों को जवाबदेह बनाना होगा। सत्य निकेतन की त्रासदी को जुलाई 2024 के पुराने राजेंद्र नगर हदसे से अलग करके नहीं देखा जा सकता। वहां राव आईएस स्टडी सर्किल के बेसमेंट में पानी भर जाने से तीन सिविल सेवा अग्र्यर्थियों-तनीया सोनी, श्रेया यादव और नवीन डालविन की मृत्यु हुई थी।

सत्य निकेतन हादसा- जिम्मेदार अधिकारियों पर हो ठोस कार्रवाई

(ललित गर्ग)

सरकारी भवन भी सुरक्षित नहीं तो आम आदमी किस पर भरोसा करे? मई 2024 में दिल्ली के आईटीओ स्थित सेंट्रल रेवेन्यू बिल्डिंग में आग लगी थी। 46 वर्षीय ऑफिस सुपरिटेंडेंट की धुएं में दम घुटने से मृत्यु हुई थी। रिपोर्टों के अनुसार भवन पुराना था और उसमें आधुनिक फायर-स्प्रिंकलर व्यवस्था भी नहीं थी। दिल्ली के सत्य निकेतन में रविवार को पांच मंजिला छात्र-पीजी भवन का भर्भराकर गिर जाना केवल एक दर्दनाक हादसा नहीं है। यह उस व्यवस्था पर गंभीर प्रश्नचिह्न है, जो भवन बनने देती है, उसमें अनधिकृत निर्माण होने देती है, उसमें विद्यार्थियों को रहने देती है, उसकी कमजोरियों को वर्षों तक नजरअंदाज करती है और फिर उसके ढह जाने के बाद जागती है। इस हादसे में अब तक छह लोगों की मौत की सूचना है और कई लोग घायल हुए हैं। प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार भवन में बेसमेंट और कई ऊपरी मंजिलों में मरम्मत या निर्माण संबंधी काम चल रहा था। प्रशासन ने मंजिस्ट्रेट जांच और भवन मालिक के खिलाफ एफआईआर के आदेश दिए हैं। लेकिन असली सवाल यह नहीं है कि हादसे के बाद किसके खिलाफ एफआईआर होगी? असली सवाल यह है कि हादसे से पहले जिम्मेदार अधिकारी कहा थे? यदि निर्माण नियमों का उल्लंघन था, यदि भवन का स्वीकृत नक्शा नहीं था, यदि अतिरिक्त मंजिलें बनाई गई थीं, यदि बेसमेंट में निर्माण चल रहा था, यदि भवन छात्रों के रहने के लिए इस्तेमाल हो रहा था और यदि वह संरचनात्मक रूप से जोखिमपूर्ण था, तो इन सबका पता प्रशासन को तब क्यों नहीं चला जब वहां निर्माण हो रहा था? सत्य निकेतन दिल्ली विश्वविद्यालय के दक्षिणी परिसर के आसपास विद्यार्थियों का प्रमुख इलाका है। देश के विभिन्न राज्यों से हजारों युवा यहां अपने भविष्य के सपने लेकर आते हैं। वे छोटे-छोटे कमरों, पीजी और किराये के मकानों में रहकर पढ़ते हैं। उनके माता-पिता अपनी जीवनभर की कमाई का बड़ा हिस्सा बच्चों की शिक्षा पर लगाते हैं और यह विश्वास करते हैं कि राजधानी में उनका बच्चा सुरक्षित रहेगा। लेकिन जब शिक्षा की तलाश में निकला युवा एक ऐसी इमारत में पहुंचता है, जिसकी नींव ही नियमों और सुरक्षा के साथ समझौते पर टिकी हो, तो विकास की हमारी पूरी अवधारणा कठघरे में खड़ी हो जाती है और यह कोई पहली चेतावनी नहीं है। 2022 में भी सत्य निकेतन में निर्माणधीन चार मंजिला इमारत ढहने से दो मजदूरों की मौत हुई थी और चार लोग घायल हुए थे। उस समय भी निर्माण

कार्य, सुरक्षा और भवन की निगरानी पर सवाल उठे थे। लगभग चार साल बाद उसी इलाके में फिर एक बड़ी इमारत ढह गई। इसका अर्थ है कि हमने घटना से सबक लेने के बजाय घटना को एक समाचार की तरह देखा और आगे बढ़ गए। यहां भ्रष्टाचार की बात करते समय एक सावधानी भी जरूरी है। किसी अधिकारी या व्यवसायी को बिना जांच दोषी ठहराना उचित नहीं। लेकिन यदि जांच में यह सिद्ध होता है कि नियमों के विरुद्ध निर्माण को जानबूझकर नजरअंदाज किया गया, निरीक्षण में लापरवाही हुई या किसी प्रकार की मिलीभगत रही, तो जिम्मेदारी



केवल भवन मालिक तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। जिसने नियम तोड़े और जिसने नियम तोड़ने दिए-दोनों को जवाबदेह बनाना होगा। सत्य निकेतन की त्रासदी को जुलाई 2024 के पुराने राजेंद्र नगर हादसे से अलग करके नहीं देखा जा सकता। वहां राव आईएस स्टडी सर्किल के बेसमेंट में पानी भर जाने से तीन सिविल सेवा अभ्यर्थियों-तनीया सोनी, श्रेया यादव और नवीन डालविन की मृत्यु हुई थी। सबसे भयावह तथ्य यह था कि बेसमेंट का उपयोग लाइब्रेरी के रूप में हो रहा था, जबकि उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार उसे पार्किंग और स्टोरेज के लिए इस्तेमाल किया जाना था। इससे भी अधिक चिंताजनक बात सामने आई-हादसे से लगभग एक महीने पहले एक विद्यार्थी ने एमसीडी में शिकायत की थी। भारत में भवन निर्माण के लिए नियमों की कमी नहीं है। नक्शा स्वीकृति, भवन उपविधियां, अग्नि सुरक्षा, संरचनात्मक सुरक्षा, अधिभोग प्रमाणपत्र, पार्किंग, बेसमेंट के उपयोग-हर क्षेत्र के लिए नियम हैं।

है। भ्रष्टाचार वह भी है जब कोई जिम्मेदार व्यक्ति अपने कर्तव्य को जानबूझकर न निभाए। किसी अवैध निर्माण को देखकर आंखें बंद कर लेना भी व्यवस्था के प्रति अपराध है। किसी भवन को जोखिमपूर्ण जानते हुए कार्रवाई न करना भी भ्रष्ट प्रशासनिक संस्कृति का हिस्सा है। सरकारी भवन भी सुरक्षित नहीं तो आम आदमी किस पर भरोसा करे? मई 2024 में दिल्ली के आईटीओ स्थित सेंट्रल रेवेन्यू बिल्डिंग में आग लगी थी। 46 वर्षीय ऑफिस सुपरिटेंडेंट की धुएं में दम घुटने से मृत्यु हुई थी। रिपोर्टों के अनुसार भवन पुराना था और उसमें आधुनिक फायर-स्प्रिंकलर व्यवस्था भी नहीं थी। यह घटना एक और सवाल सामने रखती है-जब सरकारी भवनों में भी सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त नहीं है, तो निजी और अनधिकृत भवनों की निगरानी की स्थिति क्या होगी? मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु और देश के अन्य महानगरों में अनियोजित शहरी विस्तार लगातार बढ़ रहा है। जमीन सीमित है, जनसंख्या बढ़ रही है, किराये की मांग बढ़ रही है

और व्यावसायिक हित अधिकतम जगह का अधिकतम उपयोग चाहते हैं। ऐसे में यदि शासन मजबूत नियमन और वैज्ञानिक शहरी नियोजन नहीं करेगा तो शहर ऊपर की ओर बढ़ेगा, लेकिन उसकी सुरक्षा नीचे गिरती जाएगी। दुर्घटना के बाद वही परिचित दृश्य सामने आता है-मंत्री घटनास्थल पर पहुंचते हैं, अधिकारी बैठक करते हैं, मुआवजे की घोषणा होती है, जांच समिति बनती है, कुछ भवन सील होते हैं, कुछ गिरफ्तारियां होती हैं और कुछ दिनों तक प्रशासन सक्रिय दिखाई देता है। फिर धीरे-धीरे सब सामान्य हो जाता है। लेकिन किसी मृत विद्यार्थी के माता-पिता के लिए कुछ भी सामान्य नहीं होता। उनके लिए वह एक जांच समिति नहीं, जीवनभर का खालीपन है। उनके लिए मुआवजे की राशि उनके बेटे या बेटी का विकल्प नहीं है। वे यह जानना चाहते हैं कि उनका बच्चा सुरक्षित क्यों नहीं था? किसने सुरक्षा की गारंटी दी थी? किसने निगरानी की थी? किसने खतरे को नजरअंदाज किया था? इसलिए जांच का उद्देश्य केवल दोषी व्यक्ति ढूंढना नहीं होना चाहिए। जांच को यह भी पता लगाना चाहिए कि किस स्तर पर सिस्टम विफल हुआ। फाइल कहाँ रुकी? निरीक्षण किसने किया? शिकायत किसने दबाई? नक्शा किस आधार पर स्वीकार हुआ? अवैध निर्माण वर्षों तक कैसे चलता रहा? भवन में रहने वालों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी थी? और सबसे महत्वपूर्ण-क्या उन अधिकारियों की ही जवाबदेही तय होगी जिनकी जिम्मेदारी ही ऐसे हादसों को रोकना थी? सत्य निकेतन के मलबे से आज देश को केवल छह मौतों का आंकड़ा नहीं देखना चाहिए। वहां दबे हुए सपनों को देखना चाहिए। उन माता-पिताओं की आंखों को देखना चाहिए जिन्होंने अपने बच्चों को दिल्ली भेजते समय यह सोचा होगा कि वे पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे और परिवार का नाम रोशन करेंगे। उन सपनों की मौत केवल एक इमारत के गिरने से नहीं हुई है, वे उस मानसिकता के नीचे दबे हैं जिसमें नियमों से अधिका प्रभावशाली पैसा, सुविधा और 'सब चलता है' की संस्कृति बन जाती है। अब समय है कि सरकारें हादसों के बाद जागने की आदत छोड़ें। भवन गिरने से पहले निरीक्षण हो, पानी भरने से पहले जलनिकासी सुधरे, शिकायत मिलने के बाद कार्रवाई हो और भ्रष्टाचार होने से पहले ही उसकी गुंजाइश बंद हो। क्योंकि देश को केवल नया भारत नहीं बनाना है-उसे सुरक्षित, जिम्मेदार, ईमानदार और संवेदशील भारत भी बनाना है।

इसरो को कमजोर करने की साजिश हो रही या भारत को स्पेश सुपरपावर बनने की रणनीति पर काम चल रहा?

(नীরज कुमार दुबे)

विपक्ष ने भी इस मुद्दे को राजनीतिक मोर्चे पर उठा लिया है।

कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि स्टार्ट-अप को बढ़ावा देने के नाम पर इसरो की भूमिका सीमित की जा रही है और उसकी दशकों पुरानी क्षमताएं निजी कंपनियों को सौंपी जा सकती हैं।

क्या भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो को धीरे-धीरे निजी हाथों के हवाले किया जा रहा है, या फिर देश एक ऐसी नई अंतरिक्ष रणनीति की ओर बढ़ रहा है जिसमें इसरो शोध और सामरिक अभियानों का कमांड सेंटर बनेगा और उद्योग उत्पादन की ताकत? यही सवाल पिछले कुछ दिनों से भारतीय अंतरिक्ष जागृत के भीतर और बाहर तेज बहस का विषय बना हुआ है। अब इसरो ने स्वयं सामने आकर स्पष्ट किया है कि न तो इसरो का निजीकरण होगा और न ही उसकी भूमिका या महत्व कम किया जाएगा।

यह स्पष्टीकरण ऐसे समय आया है जब इसरो के नौ कर्मचारी संगठनों ने 4 सितंबर को इसरो अध्यक्ष वी. नारायणन को पत्र लिखकर अंतरिक्ष क्षेत्र में चल रहे सुधारों, उत्पादन गतिविधियों के निजी कंपनियों और सार्वजनिक उपक्रमों को हस्तांतरण तथा कर्मचारियों के भविष्य पर गंभीर सवाल उठाए थे। उनकी चिंता का केंद्र 21 अगस्त को आईएन एसपीएसी के अध्यक्ष पवन गोयनका की वह टिप्पणी थी, जिसमें कहा गया था कि भविष्य में इसरो प्रक्षेपण यानों का निर्माण बंद कर सकता है और उनका उत्पादन उद्योग या पीएसयू संभाल सकते हैं।

इसरो का जवाब स्पष्ट है कि भूमिका बदल रही है, महत्व नहीं। एजेंसी अब उस दिशा में अपने वैज्ञानिक संसाधन केंद्रित करना चाहती है जहां उसकी विशेषज्ञता सबसे निर्णायक है। यानि फॉटियर रिसर्च, उन्नत प्रौद्योगिकी, मानव अंतरिक्ष उड़ान, अगली पीढ़ी के प्रक्षेपण यान, गहरे अंतरिक्ष और ग्रहों के मिशन तथा राष्ट्रीय और सामरिक क्षमताएं। हम आपको बता

दें कि संचार, नेविगेशन और पृथ्वी अवलोकन के उन्नत पेलोड, सेंसर, प्रणोदन प्रणालियां और अन्य महत्वपूर्ण तकनीकें इसरो के मूल फोकस में बनी रहेंगी।

दूसरी ओर, जिन तकनीकों ने परिपक्वता हासिल कर ली है और जिनका बड़े पैमाने पर नियमित उत्पादन संभव है, उन्हें उद्योग और पीएएसयू प्रतिस्पर्धी प्रक्रियाओं के माध्यम से बढ़ा सकते हैं। इसमें परिपक्व लॉन्च



व्हीकल, नियमित उपग्रह और स्थापित अंतरिक्ष प्रणालियां शामिल हो सकती हैं। इसरो का कर्क है कि इससे उसके वैज्ञानिकों और तकनीकी विशेषज्ञों का समय उत्पादन में नहीं, बल्कि भविष्य की जटिल तकनीकों और महत्वाकांक्षी अभियानों में लगेगा।

यही इस बदलाव का सबसे बड़ा रणनीतिक अर्थ है। अंतरिक्ष शक्ति बनने के लिए इसरो को फैक्ट्री से आगे बढ़कर टेक्नोलॉजी फॉटियर पर खड़ा होना होगा। भारत ने 2030 तक सालाना 50 प्रक्षेपणों का लक्ष्य रखा है। पवन गोयनका का कहना है कि इतने बड़े पैमाने का लक्ष्य कोई एक संगठन अकेले हासिल नहीं कर सकता। इसके लिए निजी पूंजी, औद्योगिक

उत्पादन क्षमता, उद्यमिता और वैश्विक बाजार तक पहुंच जरूरी है।

यह पूरी व्यवस्था भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 और एकडीआई नीति के क्रमिक उदारीकरण से जुड़ी है। इसरो इसे निजीकरण नहीं, बल्कि इकोसिस्टम विस्तार और क्षमता गुणन पता रहा है। उद्योग, स्टार्ट-अप और अकादमिक संस्थाओं को अंतरिक्ष मूल्य श्रृंखला में शामिल कर इसरो की क्षमताओं को प्रतिस्थापित नहीं, बल्कि कई गुना करने की योजना है।

नई संरचना में विभागीय भूमिकाएं भी स्पष्ट की गई हैं। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस नीति दिशा देगा, इसरो उन्नत अनुसंधान, प्रौद्योगिकी विकास और राष्ट्रीय मिशनों का मुख्य केंद्र रहेगा, आईएन- एसपीएसी गैर-सरकारी संस्थाओं की भागीदारी को संक्षम और अधिकृत करेगा, जबकि एनएसआईएल परिपक्व क्षमताओं के व्यावसायीकरण और उद्योग-आधारित उपयोग को आगे बढ़ाएगा।

लेकिन इस परिवर्तन पर सवाल लखम नहीं हुए हैं। कर्मचारी संगठनों ने पूछा है कि नीति का कानूनी और प्रशासनिक आधार क्या है, इसका क्रियान्वयन कब होगा और मौजूदा कर्मचारियों तथा भविष्य की भर्ती पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। उनका सबसे महत्वपूर्ण तर्क है कि दशकों में विकसित इसरो की तकनीक राष्ट्रीय संपति है, इसलिए उसका हस्तांतरण पारदर्शी, जवाबदेह और सामरिक तथा सुरक्षा हितों के अनुरूप होना चाहिए।

विपक्ष ने भी इस मुद्दे को राजनीतिक मोर्चे पर उठा लिया है।

कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि स्टार्ट-अप को बढ़ावा देने के नाम पर इसरो की भूमिका सीमित की जा रही है और उसकी दशकों पुरानी क्षमताएं निजी कंपनियों को सौंपी जा सकती हैं। पार्टी नेता जयराम रमेश ने इसे इसरो के साराभाई-धवन ढांचे को कमजोर करने की प्रक्रिया बताया।

यह विवाद इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत की अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाएं अब असाधारण स्तर पर पहुंच चुकी हैं। 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, 2040 तक भारतीय मानवयुक्त चंद्र मिशन, पुनः प्रयोज्य और अगली पीढ़ी के लॉन्च सिस्टम तथा सतत चंद्र और ग्रह अन्वेषण, ये लक्ष्य साधारण व्यावसायिक विस्तार से हासिल नहीं होंगे। इसरो का कहना है कि ऐसी क्षमताओं को केवल बाजार की ताकतों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता।

हम आपको बता दें कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था फिलहाल लगभग 8.4 अरब डॉलर आंकी गई है और लक्ष्य 2033 तक इसे 44 अरब डॉलर तक पहुंचाने का है। इसलिए असली चुनौती निजी क्षेत्र बनाम इसरो नहीं, बल्कि इसरो-नेतृत्व वाले राष्ट्रीय अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र की सफलता है। रणनीतिक दृष्टि से यह भारत के लिए निर्णायक मोड़ है। अब सवाल यह है कि क्या भारत उत्पादन का विस्तार करते हुए अपनी संवेदनशील तकनीक, सामरिक स्वायत्तता और वैज्ञानिक नेतृत्व की सुरक्षित राह पाएगा। यदि संतुलन सीधे बैठे, तो निजी उद्योग इसरो की ताकत बढ़ाएगा; यदि पारदर्शिता और संस्थागत नियंत्रण कमजोर पड़े, तो राष्ट्रीय क्षमताओं के हस्तांतरण पर उभरे सवाल और गंभीर होंगे। इसरो ने फिलहाल अपना संदेश साफ कर दिया है कि वह पीछे नहीं हट रहा, बल्कि उत्पादन की जिम्मेदारियों से मुक्त होकर अंतरिक्ष की अगली सीमा पर छलांग लगाने की तैयारी कर रहा है। (इस लेख में लेखक के अपने विचार हैं।)

संक्षिप्त समाचार

मानिकचौरी हत्याकांड का खुलासा, नाबालिग समेत 3 आरोपी गिरफ्तार

रायपुर। रायपुर जिले के मानिकचौरी में हुई हत्या और लूट की सनसनीखेज वारदात का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। अभनपुर पुलिस ने मामले में एक नाबालिग समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल धारदार चाकू सहित अन्य सामान बरामद किया गया है। पुलिस के अनुसार, 4 सितंबर की रात नेदप्रकाश ध्ख उर्फ धुनु और छबी जांगड़े उर्फ धोंधी शराब पी रहे थे। पैसे खत्म होने के बाद दोनों ने राहगीरों को लूटने की योजना बनाई। रात करीब 1 बजे दोनों मोटरसाइकिल से निकले और हसदा मोड़ के पास एक राहगीर को पेट्रोल खत्म होने का बहाना बनाकर रोकने की कोशिश की। राहगीर ने बाइक नहीं रोकी तो आरोपियों ने पीछा कर उसे ओवरटेक किया और रास्ते में रोक लिया। दोनों ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। विरोध करने पर साथ मौजूद नाबालिग ने धारदार चाकू से उस पर कई वार कर दिए। गंभीर रूप से घायल व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद आरोपी मृतक का मोबाइल और 1000 रुपये नकद लूटकर फरार हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी साक्ष्य और मुखबिर तंत्र की मदद से आरोपियों तक पहुंच बनाई।

ग्राम कण्डेल में युवक की गला रेतकर हत्या का खुलासा – मामूली रंजिश बनी हत्या की वजह

रायपुर। थाना अर्जुनी क्षेत्रांतर्गत ग्राम कण्डेल में दिनांक 06 सितंबर 2026 की रात्रि करीब 09:00 बजे मामूली रंजिश एवं पूर्व विवाद के चलते युवक की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या किए जाने की घटना सामने आई थी। मृतक पारसमणी साहू, उम्र 34 वर्ष, निवासी ग्राम कण्डेल, जो राजमिस्त्री का कार्य करता था, घटना के समय गांव के गौठान स्थित बरगढ़ पेड़ के पास मौजूद था। इसी दौरान आरोपी द्वारा पूर्व विवाद एवं रंजिश के चलते उस पर धारदार हथियार से हमला किया गया। गंभीर चोट लगने एवं अत्यधिक रक्तस्राव के कारण पारसमणी साहू की मौके पर ही मृत्यु हो गई। घटना की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी निरीक्षक शरद ताम्रकार पुलिस बल के साथ तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे। प्रार्थी भारत राम साहू, मृतक के पिता की रिपोर्ट के आधार पर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध थाना अर्जुनी में अपराध क्रमांक 0/2026, धारा 103(1) बीएनएस एवं मर्ग क्रमांक 88/2026, धारा 194 बीएनएसएस के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की गई। पुलिस टीम द्वारा घटनास्थल का सूक्ष्म निरीक्षण करते हुए आवश्यक फॉरेंसिक एवं तकनीकी साक्ष्य संकलित किए गए तथा प्रत्यक्षदर्शियों, परिजनों एवं संदेहियों से लगातार पृछताछ की गई।

पत्नी की हत्या कर आत्महत्या का रूप देने की कोशिश आरोपी पति गिरफ्तार

रायपुर। एसपी धमतरी भावना पांडेय के निर्देशन में जिले में गंभीर अपराधों के खिलाफ चल रही त्वरित कार्रवाई के तहत भखारा पुलिस ने पत्नी की हत्या कर वारदात को आत्महत्या का रूप देने का प्रयास करने वाले आरोपी पति को गिरफ्तार किया है। मर्ग जांच के दौरान पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मानववध की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने मामले का खुलासा किया। जानकारी के अनुसार, थाना भखारा में मर्ग क्रमांक 47/2026 की जांच के दौरान मृतका वीणा ध्व की मौत संदिग्ध पाए जाने पर पुलिस ने परिजनों और गवाहों के बयान दर्ज किए। शव परीक्षण रिपोर्ट में चिकित्सक ने मृत्यु की प्रकृति मानववध होना बताया। इसके बाद पुलिस ने अपराध क्रमांक 109/2026, धारा 103(1) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की। जांच के दौरान पुलिस ने मृतका के पिता विवेक ध्व उर्फ गोलू (30), पिता राजकुमार ध्रुव, निवासी सुपैला, थाना भखारा से पृछताछ की। पुलिस के मुताबिक पृछताछ में आरोपी ने बताया कि पत्नी के मोबाइल पर किसी अन्य व्यक्ति से बातचीत करने की बात को लेकर विवाद हुआ था।

फर्जी डीएड से नौकरी पाने वाला शिक्षक निलंबित

रायपुर। फर्जी और कूटरचित दस्तावेज के जरिए नौकरी हासिल करने के मामले में जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। कलेक्टर कुलदीप शर्मा के निर्देश पर कसडोल विकासखंड के शासकीय प्राथमिक शाला कंजिया में पदस्थ सहायक शिक्षक (एलबी) रामेश्वर प्रसाद साहू को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार पिसौली निवासी हेमदास मानिकपुरी ने कलेक्टर जनरदन में शिकायत की थी कि रामेश्वर प्रसाद साहू ने वर्ष 2011 में फर्जी डीएड अंकसूची के आधार पर शिक्षाकर्मी वर्ग-3 के पद पर नियुक्ति प्राप्त की थी। शिकायत के मुताबिक, उन्होंने सत्र 2008 की डीएड अंकसूची, रोल नंबर 47240442 प्रस्तुत की थी। शिकायत की जांच के दौरान दस्तावेजों में ऐसी गड़बड़ी सामने आई, जिसने पूरे मामले को संदिग्ध बना दिया। शिक्षक ने 2011 में नियुक्ति हासिल करने के करीब 11 साल बाद पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय, बिलासपुर से दोबारा डीएड किया था।

साक्षरता से व्यक्ति सशक्त होता है

योजनाओं का लाभ लेने और साइबर ठगी से बचने में मिलती है मदद-मंत्री

■ हम सभी को मिलकर कोरबा को पूर्ण साक्षर जिला बनाना है – कैबिनेट मंत्री लखन लाल

■ अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत हुआ समारोह

रायपुर/ संवाददाता

अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर जिला साक्षरता विभाग, कोरबा द्वारा उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिला स्तरीय साक्षरता समारोह का आयोजन किया गया। समारोह का आयोजन साक्षर बनें, सशक्त बनें एवं उल्लास से उवल भविष्य की ओर की थीम पर किया गया।



कार्यक्रम का उद्देश्य जिले में निरक्षर व्यस्कों को साक्षर बनाने के साथ उनमें जागरूकता एवं आत्मनिर्भरता की भावना विकसित करना है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उद्योग, वाणिज्य एवं श्रम, आबकारी तथा सार्वजनिक उपक्रम मंत्री छत्तीसगढ़ शासन श्री लखन लाल देवांगन शामिल हुए। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में प्रत्येक व्यक्ति का साक्षर होना अत्यंत आवश्यक है। साक्षरता व्यक्ति को अपने अधिकारों और दायित्वों को समझने के साथ दैनिक जीवन में बैंकिंग लेन-देन, शासकीय योजनाओं

और विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को सही ढंग से समझने में सक्षम बनाती है। साक्षर व्यक्ति ठगी और धोखाधड़ी का शिकार होने से भी काफी हद तक बच सकता है। उन्होंने कहा कि आज के समय में केवल पढ़ना-लिखना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि डिजिटल रूप से भी जागरूक और साक्षर होना जरूरी है। मंत्री श्री देवांगन ने कहा कि कोरबा जिला विभिन्न क्षेत्रों में लगातार उपलब्धियां हासिल कर रहा है। साक्षरता के क्षेत्र में भी जिले को नई ऊंचाइयों तक ले जाना है। उन्होंने उम्मीद जताई कि 27 सितंबर को आयोजित होने

वाली परीक्षा के बाद कोरबा पूर्ण साक्षर जिला बनने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करेगा। उन्होंने कहा कि कोरबा को पूर्ण साक्षर जिला बनाने के लिए हम सभी को मिलकर प्रयास करना होगा। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे साक्षरता अभियान में सक्रिय सहभागिता निभाएं और अपने आसपास तथा परिवार के निरक्षर लोगों को साक्षर बनाने में सहयोग करें। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत-2047 के लक्ष्य को लेकर देश को आगे बढ़ा रहे हैं। इसी प्रकार मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय विकसित छत्तीसगढ़-2047 के लक्ष्य के साथ विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों को मूर्त रूप दे रहे हैं। इस लक्ष्य को हासिल करने में साक्षरता की महत्वपूर्ण भूमिका है। साक्षर व्यक्ति अपने अधिकारों को समझने के साथ शासन की योजनाओं का बेहतर लाभ उठा सकता है और समाज के विकास में प्रभावी योगदान दे सकता है। कटघोरा विधायक श्री प्रेमचंद पटेल ने कहा कि साक्षरता से व्यक्ति में जागरूकता आती है और रूढ़िवादिता दूर होती है।



कर्मों के कर्ज का भुगतान किए बिना सिद्ध पद की प्राप्ति संभव नहीं होता...

रायपुर। संवाददाता

जिनकुशल सूरि जैन दादाबाड़ी में बुधवार को कल्पसूत्र की पांचवी वाचना के अंतर्गत साध्वीवर्या नवकार जपेश्वरी शुभंकरा महाराज साहब ने श्रद्धालुओं को भगवान महावीर के जीवन चरित्रों व कल्याणकों का श्रवण कराया। भगवान के जन्मोत्सव के उपरांत उनका नामकरण हुआ, नाम रखा गया वर्धमान कुमार। बाल्यकाल से ही निश्रा में दीक्षा ग्रहण करने, गणधर गौतम स्वामी व भगवान महावीर के मध्य धर्म संवाद, भगवान के निर्वाण एवं गौतम स्वामी को कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति आदि कथानकों का श्रवण करते हुए कल्पसूत्र की पांचवी वाचना पूर्ण की। जैन श्वेताम्बर चातुर्मास समिति के अध्यक्ष विमलचंद मालू, उपाध्यक्ष पारस पारख व चातुर्मास समिति के प्रचार प्रसार प्रभारी तरूण कोचर ने बताया कि आज प्रातः धर्मसभा में साध्वी भगवंत के मुख से जब भगवान महावीर के दीक्षा कल्याणक का प्रसंग श्रवण कराया जा रहा था।

मातृत्व का संबल बनी मिनीमाता महतारी जतन योजना महिलाओं के खातों में सीधे पहुंची 20 20 हजार रुपए की सहायता राशि.....

■ प्रसूता महिलाओं को पोषण, स्वास्थ्य और नवजात की देखभाल में मिली आर्थिक राहत

रायपुर/ संवाददाता

मातृत्व का संबल बनी ‘मिनीमाता महतारी जतन योजना’राज्य शासन के श्रम विभाग द्वारा संचालित ‘मिनीमाता महतारी जतन योजना’ सुदूर वनांचल और ग्रामीण क्षेत्रों की श्रमिक महिलाओं के लिए मातृत्व के कठिन दौर में आर्थिक संबल का मजबूत माध्यम



बन रही है। योजना का उद्देश्य मातृत्व का सम्मान करते हुए प्रसूता महिलाओं और उनके नवजात शिशुओं के बेहतर पोषण एवं स्वास्थ्य के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से सहायता राशि सीधे हितग्राही महिलाओं के बैंक खातों

में पहुंचने से योजना में पारदर्शिता के साथ-साथ जरूरत के समय तत्काल आर्थिक सहयोग सुनिश्चित हो रहा है। इस योजना का सकारात्मक प्रभाव बस्तर जिले के सुदूर ग्रामीण अंचलों में भी दिखाई दे रहा है। बकावंड विकासखंड के ग्राम सोनपुर निवासी श्रीमती बालिका के लिए दूसरी संतान के जन्म के अवसर पर योजना से मिली सहायता आर्थिक राहत का आधार बनी। बैंक खाते में सीधे सहायता राशि पहुंचने से प्रसव के बाद जच्चा और बच्चा दोनों के खान-पान, पोषण एवं आवश्यक स्वास्थ्य देखभाल से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने में परिवार को काफी मदद मिली।

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ आधुनिक सुविधाओं पर जोर

बेहतर शिक्षा के साथ संस्कार प्रदान करना हमारी प्राथमिकता

■ वनांचल की प्रतिभाओं को उचित मार्गदर्शन और अवसर मिलने से खुलेगे सफ़रता के नए द्वार

रायपुर/ संवाददाता

वनांचल और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। आवश्यकता केवल प्रतिभाओं को उचित मार्गदर्शन, संसाधन और अवसर उपलब्ध कराने की है। विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा के साथ अच्छे संस्कार, अनुशासन, राष्ट्रप्रेम और जिम्मेदारी का भाव देना भी जरूरी है। उक्त बातें स्कूल शिक्षा मंत्री श्री गजेंद्र यादव ने जिला प्रवास के दौरान पीएम श्री आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय, मानपुर में आयोजित दैनिक भास्कर प्रतिभा सम्मान समारोह में कही।



दिशा में आगे बढ़ चुका है। अब नई ऊर्जा और नए संकल्प के साथ क्षेत्र में विकास एवं निर्माण के कार्यों को गति देने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि किसी भी समाज के विकास की सबसे मजबूत नींव शिक्षा है। वनांचल और ग्रामीण क्षेत्रों में भी प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की

भरमार है। यहां के विद्यार्थी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं सहित शैक्षणिक क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर अपनी प्रतिभा साबित कर रहे हैं। ऐसे विद्यार्थियों को आगे बढ़ाने के लिए कैरियर काउंसलिंग की व्यवस्था की जाएगी, जिससे विद्यार्थी अपनी रुचि और क्षमता के अनुरूप

छत्तीसगढ़ी को आठवीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए सकारात्मक पहल

■ राज्यपाल श्री रमेन डेका से छत्तीसगढ़ी भाषाविदों ने की भेंट

रायपुर/ संवाददाता

राज्यपाल श्री रमेन डेका से आज लोक भवन में छत्तीसगढ़ी भाषाविदों ने भेंट कर छत्तीसगढ़ी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने तथा इसके संरक्षण, संवर्धन एवं विकास के संबंध में चर्चा की। भाषाविदों ने राज्यपाल को छत्तीसगढ़ी भाषा की प्राचीनता, समृद्ध साहित्यिक परंपरा, व्याकरण, शब्दकोश एवं मानकीकरण की प्रक्रिया के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ी प्रदेश की राजभाषा एवं प्रमुख संपर्क भाषा है और लगभग डेढ़ करोड़ लोग इसका प्रयोग करते हैं। राज्यपाल श्री डेका ने स्वयं पहल करते हुए इस विषय पर सार्थक चर्चा की। छत्तीसगढ़ी भाषा के विकास और इसे आठवीं अनुसूची में शामिल कराने की दिशा में

सकारात्मक पहल करते हुए कहा कि इसके लिए एक समिति का गठन किया जाएगा। समिति द्वारा छत्तीसगढ़ी भाषा के इतिहास, साहित्य, व्याकरण, शब्दकोश एवं अन्य संदर्भ सामग्री का व्यवस्थित संकलन किया जाएगा। इसके लिए विषय के विद्वानों एवं विशेषज्ञों से आवश्यक जानकारी और सुझाव भी लिए जाएंगे। राज्यपाल ने इस संदर्भ में असमिया और बोडो भाषाओं को आठवीं अनुसूची में शामिल किए जाने का उदाहरण भी दिया। भाषाविदों ने बताया कि छत्तीसगढ़ी में 15 वीं शताब्दी से साहित्य सृजन की समृद्ध परंपरा रही है। कविता, खंडकाव्य, कहानी, उपन्यास, नाटक, आलोचना एवं पत्रकारिता सहित विभिन्न विधाओं में प्रचुर सामग्री उपलब्ध है। छत्तीसगढ़ी का व्याकरण वर्ष 1890 में तथा पहला शब्दकोश वर्ष 1939 में तैयार हुआ। वर्ष 1924 में पहला छत्तीसगढ़ी उपन्यास 'होहू के कहनी' प्रकाशित हुआ। पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा जेल से हस्तलिखित छत्तीसगढ़ी पत्रिका 'दुलरवा' का प्रकाशन भी किया गया था।

डकैती की योजना बनाते पांच आरोपी गिरफ्तार किए

रायपुर। राजधानी रायपुर में अलग-अलग थाना क्षेत्रों में चोरी, झपटमारी, अवैध शराब और मादक पदार्थों से जुड़े मामलों में पुलिस ने कार्रवाई की है। खम्हारडीह पुलिस ने कचना तालाब के पास खेल मैदान में डकैती की योजना बनाते पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से धारदार हथियारों सहित अन्य सामान बरामद किया गया है। वहीं राजेंद्र नगर पुलिस ने गांजा और अवैध शराब के मामले में कार्रवाई की, जबकि डोंडी नगर पुलिस ने नशीली प्रतिबंधित गोलीयां जब्त की हैं। खम्हारडीह थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कचना तालाब के पास कुछ लोग डकैती की योजना बना रहे हैं। सूचना पर पुलिस टीम ने मौके पर दबिश दी। पुलिस के मुताबिक

मौके पर पांच आरोपी मिले, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों के कब्जे से एक मोटरसाइकिल, एक टाटा एस वाहन, तीन धारदार चाकू, दो कैंची, स्टील का पाइप और लोहे का गंडासा बरामद किया गया। मामले में पुलिस ने बीएनएस की संबंधित धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की है। सरस्वती नगर थाना क्षेत्र में महोबा बाजार ओवरब्रिज के पास मोबाइल झपटमारी का मामला सामने आया। पुलिस के अनुसार जितेश साहू मोबाइल पर बात करते हुए पैदल जा रहे थे। इसी दौरान पीछे से मोटरसाइकिल सवार अज्ञात व्यक्ति आया और उनके हाथ में रखा वीवो कंपनी का मोबाइल फोन, जिसकी कीमत करीब 20 हजार रुपये थी, झपटकर फरार हो गया।

संक्षिप्त समाचार

सरकारी सब्सिडी से आसान हुई राह पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना

रायपुर। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी ‘पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना’ छत्तीसगढ़ के दत्तेवाड़ा जिले में नागरिकों के जीवन में बड़ा बदलाव ला रही है। इस योजना के माध्यम से लोग न केवल स्वच्छ ऊर्जा अपना रहे हैं, बल्कि अपने बिजली खर्च में भी उल्लेखनीय बचत कर रहे हैं। दत्तेवाड़ा जिले के बड़े तुमनार निवासी श्री मोफलनार माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक श्री कैलाश कुमार देवांगन इसके प्रेरक उदाहरण बने हैं। कैलाश कुमार देवांगन अपने गांव के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने मार्च 2026 में इस योजना का लाभ उठाते हुए अपने घर की छत पर 3 किलोवाट क्षमता का सोलर रूफटॉप प्लांट स्थापित कराया। उन्होंने बताया कि पहले उनके 4 सदस्यीय परिवार का मासिक बिजली बिल करीब 1,000 से 1,200 (लगभग 200 यूनिट खपत) आता था। लेकिन सोलर प्लांट लगने के बाद से उनका बिजली बिल पूरी तरह समाप्त हो गया है। श्री देवांगन को मार्च माह में आयोजित शिक्षकों की एक बैठक के दौरान इस योजना की विस्तृत जानकारी मिली थी। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा दी जा रही सब्सिडी इस योजना की सबसे बड़ी खासियत है, जिससे आम परिवारों के लिए सौर ऊर्जा संयंत्र लगाना बेहद आसान हो गया है।

22 सितंबर से थम सकते हैं बसों के पहिए, 12 हजार बसों की हड़ताल का ऐलान

रायपुर। छत्तीसगढ़ में 22 सितंबर से यात्रियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर यातायात महासंघ ने प्रदेशव्यापी अनिश्चितकालीन महाबंद का ऐलान किया है। महासंघ के मुताबिक हड़ताल के दौरान प्रदेश की करीब 12 हजार बसों के पहिए थम जाएंगे, जिससे रोजाना सफ़र करने वाले लगभग 4 लाख 80 हजार यात्रियों पर सीधा असर पड़ने की संभावना है। बस ऑपरेटर यात्री किराए में वृद्धि, सिंगल स्लीपर बसों पर सिंगल टैक्स लागू करने और ई-बसों के संचालन को केजल नगर निगम सीमा तक सीमित करने सहित 9 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। महासंघ का कहना है कि मांगों को लेकर विभागीय मंत्री से मुलाकात भी की गई, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकला है। आंदोलन के तहत प्रदेशभर के करीब 800 बस ऑपरेटर अपनी बसें बस स्टैंड पर खड़ी कर विरोध प्रदर्शन करेंगे। यातायात संघ के अध्यक्ष अनवर अली ने कहा कि सरकार और विभाग के समक्ष कई बार अपनी मांगें रखी गई हैं, लेकिन मांगों पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं होने के कारण महासंघ को अनिश्चितकालीन महाबंद का निर्णय लेना पड़ा है।

पिकअप पलटने से खुला पशु तस्करी का राज, 5 भैंस बरामद, 3 आरोपी गिरफ्तार

रायपुर। नगरी थाना क्षेत्र में भैंस तस्करी का मामला सामने आया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक पिकअप वाहन से 5 भैंसों को बरामद किया है। मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के मुताबिक, ग्राम कर्राघाटी-चमेदा मार्ग पर पांच भैंसों को एक छोटी पिकअप में भरकर ले जाया जा रहा था। इसी दौरान वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे की सूचना पर नगरी पुलिस मौके पर पहुंची। वाहन की तलाशी लेने पर उसमें पांच भैंसें मिलीं। पुलिस जांच में सामने आया कि पशुओं को पिकअप में अमानवीय तरीके से टूँसकर ले जाया जा रहा था। वहीं, परिवहन से संबंधित वैध दस्तावेज भी आरोपियों के पास नहीं मिले। पुलिस के अनुसार, पाइप भाटा निवासी ऑंकार कुर्रें और उसके दो साथी भैंसों को नवरंगपुर स्थित कत्तखाने ले जा रहे थे। हादसे के बाद पुलिस ने वाहन और पशुओं को अपने कब्जे में लिया तथा तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ पशु क़रूरता अधिनियम और छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम के तहत अपराध दर्ज किया है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि भैंसों को कहाँ से लाया गया था और तस्करी के इस नेटवर्क में और कौन लोग शामिल हैं।

नाबालिग से छेड़छाड़, घर में घुसकर मारपीट और धमकी देने वाला आरोपी गिरफ्तार

रायपुर। नाबालिग बालिका से छेड़छाड़, घर में अनधिकृत प्रवेश, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के मामले में सुरगी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव अंकिता शर्मा (भा.पु.से.) के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर के मार्गदर्शन तथा नगर पुलिस अधीक्षक वैशाली जैन (भा.पु.से.) के पर्यवेक्षण में बच्चों एवं महिलाओं के विरुद्ध अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए चलाया जा रहे अभियान के तहत की गई। पुलिस के अनुसार, 7 सितंबर 2026 को एक नाबालिग पीड़िता ने पुलिस चौकी सुरगी में शिकायत दर्ज कराई। पीड़िता ने बताया कि सुबह करीब 9:15 बजे आरोपी कमलेश साहू उसके घर में जबरन घुस आया और उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने 21 नवचयनित सहायक संचालकों को सौंपे नियुक्ति पत्र

सुनियोजित शहरीकरण से मजबूत होगी विकसित छत्तीसगढ़ की नींव

■ भविष्य के छत्तीसगढ़ के शहरों को आकार देने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी अब युवा टाउन प्लानर्स के कंधों पर – मुख्यमंत्री

रायपुर/ संवाददाता

शहरों का विकास केवल वर्तमान आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों की जरूरतों के अनुरूप किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कार्यक्रम में नगर तथा ग्राम निवेश विभाग के 21 नवचयनित सहायक संचालकों (योजना) को नियुक्ति पत्र प्रदान करने के बाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह बात कही। मुख्यमंत्री श्री साय ने सभी नवचयनित अधिकारियों को उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि राज्य निर्माण के बाद पहली बार



नगर तथा ग्राम निवेश विभाग में एक साथ इतनी बड़ी संख्या में सहायक संचालकों की नियुक्ति हुई है। यह नियुक्ति विभाग की कार्यक्षमता बढ़ाने के साथ प्रदेश में तेजी से हो रहे शहरीकरण को सुनियोजित दिशा देने में महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। मुख्यमंत्री श्री साय ने नवचयनित अधिकारियों के माता-पिता और परिजनों को भी विशेष रूप से बधाई दी। उन्होंने कहा कि बच्चों को अच्छी शिक्षा देकर योग्य बनाना और उन्हें जिम्मेदार पद पर प्रदेश तथा जनता की सेवा करते देखना प्रत्येक माता-पिता के लिए गर्व और

प्रसन्नता का अवसर होता है। आज इन युवाओं के जीवन में नई जिम्मेदारी की शुरुआत हो रही है और इसके साथ उनके परिवारों की अपेक्षाएं तथा प्रदेश की आशाएं भी जुड़ी हुई हैं। 'मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ के गठन को 25 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इस अवधि में नगर तथा ग्राम निवेश विभाग में कुल 17 सहायक संचालकों की नियुक्ति हुई थी, जबकि आज एक साथ 21 युवा अधिकारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए जा रहे हैं। इससे स्पष्ट है कि राज्य सरकार भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में

शिक्षकों के समर्पण से बदले बच्चों के दिन,राज्यपाल पुरस्कार से सम्मानित.....

रायपुर/ संवाददाता

सरकारी स्कूलों की तस्वीर बदलने के लिए हमेशा बड़े संसाधनों की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि साफ नीयत, नई सोच और बच्चों के भविष्य के प्रति सच्चा समर्पण ही सबसे बड़ा बदलाव ला सकता है। धमतरी जिले के तीन शिक्षकों ने अपनी इसी निष्ठा और नवाचार से यह साबित कर दिखाया है। अपनी जेब से खर्च, अतिरिक्त समय और पालकों व शिक्षकों की सहभागिता के बल पर इन्होंने न केवल सरकारी स्कूलों में छात्र संख्या बढ़ाई, बल्कि इन्हें बच्चों और अभिभावकों की पहली पसंद भी बना दिया। कलेक्टर ने इन शिक्षकों को पहल को पूरे जिले के लिए गौरव और शिक्षा जगत के लिए एक प्रेरणास्रोत बताया है। इन नवाचारी शिक्षकों के प्रयासों से जिले के प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा के स्तर में अद्भुत सुधार देखने को मिला है। शासकीय प्राथमिक शाला धौराभाठा के शिक्षक

श्री लीलाराम साहू ने खेल-खेल में और टीएलएम आधारित शिक्षण पद्धति को अपनाया, जिससे बच्चों में सीखने की रुचि बनी। उनके मार्गदर्शन का ही परिणाम है कि कभी सीमित छात्र संख्या वाले इस स्कूल से अब तक 23 बच्चों का चयन जवाहर नवोदय विद्यालय एवं एकलव्य विद्यालय में हो चुका है। 'पढ़ई तुहर दुआर' कार्यक्रम में भी उनके योगदान को राज्य स्तर पर सराहना मिली है। वहीं, शासकीय माध्यमिक शाला लुगे की शिक्षिका श्रीमती रंजीता साहू ने तकनीक और जनभागीदारी का एक अनोखा मॉडल पेश किया। उन्होंने संसाधनों की कमी को आड़े न आने देते हुए 'मैं हूँ गुरुक' अभियान की शुरुआत की, जिसके माध्यम से जिले के 150 विद्यालयों में स्मार्ट टीवी उपलब्ध कराए गए। इसके साथ ही उन्होंने 300 स्कूलों में गणित वर्णमाला पहुँचाने और लगभग 11 हजार बच्चों को कॉपी-किताबें व पेन वितरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

छत्तीसगढ़ में जलेंगे 36 लाख आशीर्वाद के दीये 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलेगा सेवा संकल्प अभियान....

रायपुर/ संवाददाता



ने मंगलवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में आयोजित पत्रकार वार्ता में आयोजित कार्यक्रम के प्रति आभार व्यक्त किया जाएगा और 'विकसित भारत 2047' का संकल्प लिया जाएगा। 7 अक्टूबर को जिला मुख्यालयों के प्रमुख चौराहों पर विशेष मशाल स्थापित की जाएगी। इसी दिन प्रमुख चौकों पर बड़ी एलईडी स्क्रीन लगाई जाएंगी।

दहेज की कुरीति पर रंगमंच से प्रहार, ‘मया के मुंदरी’ ने जगाई सामाजिक चेतना

मया के मुंदरी’ ने दहेज प्रथा के खिलाफ बुलंद की आवाज

■ रंग परब नाट्य श्रृंखला’ का भव्य शुभारंभ — तीन दिनों तक रोजाना होंगी दो नाट्य प्रस्तुतियां

■ सामाजिक सरोकारों से लेकर पौराणिक कथाओं तक दिखेगा रंगमंच का विविध संसार

रायपुर/ संवाददाता

संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित तीन दिवसीय ‘रंग परब नाट्य श्रृंखला’ का शुभारंभ बुधवार को मेकाकाशी मंच, महंत धासीदास संग्रहालय परिसर, सिविल लाइंस, घड़ी चौक

बिहान योजना ने दिया आजीविका का सहारा मुर्गी पालन से दत्तेवाड़ा की रामबती ने कमाए 25 हजार रुपये

रायपुर। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (‘बिहान’) के तहत संचालित इंटोग्रेटेड फार्मिंग क्लस्टर योजना छत्तीसगढ़ के ग्रामीण इलाकों में महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की दिशा में एक प्रभावी जरिया बन रही है। दत्तेवाड़ा जिले के कुआकोंडा और दत्तेवाड़ा विकासखंडों में बीते डेढ़ वर्षों से लागू इस योजना के जरिए लगभग 2,200 परिवारों को आजीविका के नए साधनों से जोड़ा जा चुका है। दत्तेवाड़ा जिले के कुआकोंडा विकासखंड के ग्राम मुड़ापारा की निवासी रामबती नाग ने इस योजना का लाभ उठाकर मुर्गी पालन की शुरुआत की। जिला प्रशासन के सहयोग से उन्हें जून माह में 780 प्रति चूजा की दर से 100 चूजे और दाना उपलब्ध कराया गया था। शुरुआती दौर में बीमारी के कारण करीब 25 से 30 चूजों की मृत्यु हो जाने से रामबती को झटका जरूर लगा, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। बचे हुए चूजों का बेहतर रखरखाव और देखभाल करके उन्होंने अब तक करीब 725,000 की शुद्ध आय अर्जित कर ली है। रामबती अपने तैयार मुर्गों को 7500 प्रति किलो की दर से बेचती हैं, जिनका औसतन वजन 1 से 3 किलोग्राम तक होता है।

रायपुर में वाहन चोरी से लेकर चाकूबाजी तक की घटनाएं....

रायपुर। संवाददाता

राजधानी रायपुर में अलग-अलग थाना क्षेत्रों में चोरी, चाकूबाजी, मारपीट, धमकी और सड़क दुर्घटनाओं से जुड़े कई मामले सामने आए हैं। पुलिस ने शिकायतों के आधार पर संबंधित धाराओं में अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तेलीबांधा थाना क्षेत्र में एचडीएफसी बैंक के सामने खड़ी एफ्टिवा चोरी हो गई। शिकायतकर्ता स्वप्नल जैन के मुताबिक उनकी सीजी 04 बीवाई 8045 नंबर की एफ्टिवा, जिसकी कीमत करीब 5 हजार रुपये थी, को अज्ञात चोर ले गया। पुलिस ने बीएनएस की धारा 303(2) के तहत मामला दर्ज किया है। खमतराई थाना क्षेत्र के दही हांडी मैदान, श्रीनगर में खड़ी होंड

एफ्टिवा मोपेड चोरी होने की शिकायत दर्ज हुई है। रवि शंकर साहू की सीजी 04 एलजेड 9546 नंबर की एफ्टिवा, जिसकी कीमत करीब 15 हजार रुपये बताई गई है, अज्ञात चोर लेकर फार हो गया। मौदहापारा थाना क्षेत्र के मेकाहारा अस्पताल एंबुलेंस स्टैंड और देवेन्द्रनगर थाना क्षेत्र में अलग-अलग मामलों में आरोपियों पर चाकू लेकर आम लोगों को आतंकित करने का आरोप है। दोनों मामलों में पुलिस ने आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया है। वहीं उरला थाना क्षेत्र के बुधवारी बाजार, बीरगांव में भी चाकू लेकर लोगों को डराने के आरोप में मामला दर्ज किया गया। गणेश नगर खम्हारडीह में कुशलता से जुड़ी बात को लेकर विवाद हुआ।

दहेज की कुरीति पर रंगमंच से प्रहार, ‘मया के मुंदरी’ ने जगाई सामाजिक चेतना



करने का सशक्त माध्यम है। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के कवि मीर अली मीर, वरिष्ठ पत्रकार एवं छायाकार श्री दीपेंद्र दीवान, साहित्यकार श्री विजय मिश्रा, पिप्पिम बोर्ड की सदस्य श्रीमती प्रसन्ना अवस्थी तथा समाजसेवी

श्री उदयभान चौहान विशेष रूप से उपस्थित रहे। नाट्य श्रृंखला की पहली प्रस्तुति ‘मया के मुंदरी’ रही, जिसका मंचन रिखी क्षत्रिय एवं समूह द्वारा किया गया। नाटक ने शुरुआत से ही दर्शकों का ध्यान सदस्य श्रीमती प्रसन्ना अवस्थी की ओर आकर्षित

किया। दहेज प्रथा पर केंद्रित इस प्रस्तुति में दिखाया गया कि किस तरह धन-संपत्ति का लालच विवाह जैसे पवित्र रिस्ते को रिस्ते से सौंदरबाजी में बदल देता है। नाटक में दहेज के लालची पिता के चरित्र के माध्यम से यह दिखाया गया कि बेटे का विवाह उसके लिए संस्कार, प्रेम और पारिवारिक संबंधों का अवसर न रहकर धन-संपत्ति और गाड़ी हासिल करने का माध्यम बन जाता है। दहेज के लालच की यह मानसिकता केवल सामाजिक और नैतिक मूल्यों को कमजोर नहीं करती, बल्कि परिवार और रिश्तों की बुनियाद को भी प्रभावित करती है। कहानी का सबसे प्रभावशाली पक्ष यह रहा कि स्वामिनी बेटा और उसकी मां दहेज के खिलाफमजबूती से खड़े होते हैं। वे गरीब लड़की और उसके पिता का समर्थन करते हैं तथा विवाह को आर्थिक लेन-देन से अलग मानवीय संबंध के रूप में स्थापित करने का प्रयास करते हैं।

नारी शक्ति सम्मान से सम्मानित हुई डालिमा गौर सुकमा के उत्कृष्ट कार्यों को भी मिली पहचान

सुकमा। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की रजत जयंती के अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली प्रदेश की 50 महिलाओं एवं संस्थाओं को ‘नारी शक्ति सम्मान’ से सम्मानित किया गया। विगत दिनों अटल बिहारी वाजपेयी ऑडिटोरियम, रायपुर में आयोजित समारोह में महिला सशक्तिकरण एवं समाजहित के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्यों के लिए डालिमा गौर को विशेष रूप से सम्मानित किया गया।

डालिमा गौर के उत्कृष्ट कार्यों को मिली सम्मान की पहचान

डालिमा गौर को उनके द्वारा महिला सशक्तिकरण, समाजहित, नेतृत्व एवं सकारात्मक सामाजिक बदलाव की दिशा में किए जा रहे उत्कृष्ट एवं प्रेरणादायी कार्यों के लिए ‘नारी शक्ति सम्मान-2026’ से नवाजा गया। सम्मान के रूप में उन्हें प्रशस्ति-पत्र एवं सम्मान प्रतीक प्रदान किया गया। यह सम्मान डालिमा गौर के सामाजिक सरोकारों के

प्रति समर्पण और महिलाओं के हित में किए जा रहे कार्यों को मिली महत्वपूर्ण पहचान है। उनके इस सम्मान से परिवार, शुभचिंतकों एवं क्षेत्रवासियों में हर्ष का माहौल है।

सखी वन स्टॉप सेंटर सुकमा को भी मिला सम्मान

इसी समारोह में महिलाओं की सुरक्षा एवं सम्मान के क्षेत्र में सखी वन स्टॉप सेंटर, सुकमा एवं महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला सुकमा द्वारा किए जा रहे उत्कृष्ट कार्यों को भी सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय द्वारा सखी वन स्टॉप सेंटर सुकमा को ‘नारी शक्ति सम्मान’



दीपिका शोरी ने की डालिमा गौर के कार्यों की सराहना

छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की सदस्य एवं बस्तर संभाग प्रभारी अधिवक्ता दीपिका शोरी ने डालिमा गौर को बधाई देते हुए कहा— डालिमा गौर द्वारा समाजहित, महिला सशक्तिकरण और सकारात्मक बदलाव की दिशा में किए जा रहे उत्कृष्ट कार्य अत्यंत सराहनीय एवं प्रेरणादायी हैं। उनका यह सम्मान निश्चित रूप से अन्य महिलाओं को भी समाज के लिए बेहतर कार्य करने की प्रेरणा देगा। उन्होंने सखी वन स्टॉप सेंटर सुकमा को मिले सम्मान के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग की पूरी टीम को भी बधाई दी और कहा कि महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और सशक्तिकरण के लिए किए जा रहे ऐसे प्रयास समाज में सकारात्मक बदलाव की मजबूत नींव रखते हैं।

प्रदान किया गया। यह सम्मान महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, संरक्षण, सहायता तथा उन्हें आवश्यक सेवाओं से जोड़ने की दिशा में सुकमा जिले में किए जा रहे कार्यों की सराहना है।

अण्डर ट्रायल रिव्यू कमेटी, मॉनिटरिंग सेल एवं नेशनल लोक अदालत के संबंध में कोण्डागांव जिले के अधिकारियों का बैठक हुआ सम्पन्न



कोंडागांव। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव खिलावन राम रिगरी के अध्यक्षता एवं उनकी उपस्थिति में अण्डर ट्रायल रिव्यू कमेटी एवं मॉनिटरिंग सेल एवं हिट एण्ड रन व नेशनल लोक अदालत की बैठक मध्यस्थता कक्ष में आयोजित की गई। बैठक में अपर जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश विक्रम प्रताप चंद्रा, कलेक्टर कोंडागांव नुरुर-रशिा पन्ना, पुलिस अधीक्षक पंकज चंद्रा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रेशमा बैरगी पटेल, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गायत्री साय, लोक अभियोजन

अधिकारी तथा लोक निर्माण विभाग, प्रशासनिक अधिकारी व न्यायालय अधीक्षक सम्मिलित रहे। अण्डर ट्रायल रिव्यू कमेटी- अण्डर ट्रायल रिव्यू कमेटी की बैठक के दौरान ऐसे बंदियों के मामलों पर विशेष रूप से चर्चा की गई, जो लंबे समय से विचाराधीन हैं, जिनकी जमानत हो चुकी है परंतु वे, जमानत की शर्तें पूरी नहीं कर पा रहे हैं, अथवा जिनकी सजा की अधिकतम अवधि के सापेक्ष दे पर्याप्त समय जेल में बिता चुके हैं। न्यायाधीश ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि पात्र बंदियों के मामलों में त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित की जाए तथा

विधि के अनुरूप उन्हें राहत प्रदान की जाए। इसके साथ ही, बंदियों के अधिकारों की सुरक्षा एवं न्याय तक उनकी सुगम पहुंच सुनिश्चित करने पर भी बल दिया गया। मॉनिटरिंग सेल-मॉनिटरिंग सेल की बैठक में नवीन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय भवन निर्माण कार्य प्रारंभ करने की प्रक्रिया शीघ्रता से करने हेतु प्रधान न्यायाधीश द्वारा कलेक्टर कोण्डागांव को निर्देश दिए गए। साथ ही मेगा ड्राइव के तहत ग्राम तोतर में प्रत्येक सप्ताह के दिन गुरुवार एवं शुक्रवार को अन्य विभाग के द्वारा कैप लगवाने में सहयोग किए जाने एवं संबंधित विभाग को कैप लगावाए जाने हेतु निर्देशित किये जाने के संबंध में चर्चा की गई। नेशनल लोक अदालत 12 सितम्बर को आयोजित नेशनल लोक अदालत में राजस्व मामलों को अधिक से अधिक संख्या में रखकर मामलों को निपटारा करने हेतु न्यायाधीश महोदय द्वारा निर्देशित किया गया साथ ही पुलिस विभाग को ट्रैफिक चालान को नेशनल लोक अदालत में रखे जाने हेतु निर्देशित किया गया।

प्रधानमंत्री आवास योजना के अपूर्ण आवास 30 सितंबर तक पूर्ण कराने के निर्देश

नारायणपुर। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 1.0 के अंतर्गत अपूर्ण आवासों को शीघ्र पूर्ण कराने के उद्देश्य से नगर पालिका परिषद नारायणपुर में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में नगर पालिका क्षेत्र के ऐसे हिताग्रहियों के आवास निर्माण की प्रगति की समीक्षा की गई, जिनके आवास अभी तक पूर्ण नहीं हो सके हैं। बैठक में नगर पालिका परिषद अध्यक्ष इंद्र प्रसाद बघेल, पार्षदगण संजय नंदी, रमेशिला नाग, कृति पोटाई, संतोष गोदा, कमलापति मिश्र एवं कौशल बघेल, मुख्य नगर पालिका अधिकारी रामचंद्र यादव तथा अभियंता बसंत कुजाम उपस्थित रहे। बैठक के दौरान अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों ने अपूर्ण आवासों की स्थिति की जानकारी ली। हिताग्रहियों को निर्माण कार्य में तेजी लाने तथा शेष कार्य को निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने के लिए आवश्यक समझाइश एवं मार्गदर्शन दिया गया। नगर



पालिका द्वारा हिताग्रहियों को निर्देशित किया गया कि वे अपने-अपने अपूर्ण आवासों का निर्माण कार्य 30 सितंबर तक अनिवार्य रूप से पूर्ण करें, ताकि उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना 1.0 का लाभ निर्धारित समय-सीमा में प्राप्त हो सके। संबंधित कर्मचारियों को हिताग्रहियों से निरंतर संपर्क बनाए रखने तथा आवास निर्माण कार्य की प्रगति की नियमित निगरानी करने के निर्देश दिए गए। नगर पालिका परिषद ने योजना के तहत शेष आवासों को समय-सीमा में पूर्ण कराने के लिए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने की बात कही।

हथियार छोड़ अपनाया हुनर, पुनर्वास नीति से बदली रानू राम की जिंदगी

कोंडागांव। कभी माओवादी संगठन से जुड़े ग्राम ठेंटी मड़ानार पंचायत मुंगवाल निवासी रानू राम नेताम ने अब हिंसा का रास्ता छोड़कर विकास और सामान्य जीवन की राह अपना ली है। केंद्र और राज्य सरकार की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर रानू राम ने माओवादी संगठन से आत्मसमर्पण किया। इसके बाद शासन की पुनर्वास नीति के तहत उन्हें सुरक्षित वातावरण में रहते हुए अपनी रूचि के अनुसार प्रशिक्षण प्राप्त करने और समाज की मुख्यधारा से जुड़कर सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर मिला। आत्मसमर्पण के बाद रानू राम नेताम पुनर्वास केंद्र में रहकर अपने भविष्य को संभारने के लिए प्रशिक्षण प्राप्त करने लगे। इसी दौरान उन्होंने लाइवलीहुड कॉलेज में दुर्घटियों का प्रशिक्षण लिया। प्रशिक्षण के दौरान उन्होंने वाहन चलाने की बारिकियां



सीखीं और सफलतापूर्वक अपना प्रशिक्षण पूरा किया। रानू राम बताते हैं कि अब वे पूरी तरह से गाड़ी चलाना सीख चुके हैं और आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद रानू राम को सिक्योरिटी गार्ड के रूप में रोजगार का अवसर मिला और वर्तमान में वे सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहे हैं। वे बताते हैं कि यह नौकरी उनके जीवन में एक नया बदलाव लेकर आई है। नियमित रोजगार

मिलने से उन्हें अपने परिवार की जिम्मेदारियां निभाने में मदद मिल रही है और भविष्य को लेकर उनका आत्मविश्वास भी बढ़ा है। रानू राम कहते हैं कि उनकी इच्छा थी कि वे अपने परिवार के साथ समय बिताने के साथ-साथ घर के कामकाज में भी हाथ बंटाने हैं। नौकरी के साथ अपने परिवार और घर की जिम्मेदारियों को निभाते हुए वे अब आगे बढ़ रहे हैं। रानू राम के जीवन में बदलाव केवल रोजगार तक सीमित नहीं हैं। शासन की योजनाओं का लाभ लेकर वे अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को और मजबूत बनाने की दिशा में भी प्रयास कर रहे हैं। उनके घर में पहले से ट्यूबवेल था, लेकिन सिंचाई के लिए बिजली और अन्य संसाधनों की आवश्यकता रहती थी।

ठगों और दलालों के जाल में फंसा कांकेर का एक और किसान 18 लाख में बिकी पुश्तैनी जमीन, ट्रैक्टर भी जल्ल, हाथ बचे सिर्फ 15 हजार

भानुप्रतापपुर। बैंकों के चक्कर काटते सीधे-साधे किसानों को अपनी मीठी बातों में फंसाकर लूटने वाले गिरोह का एक और खोफनाक कारनामा सामने आया है। दुर्गकोदल ब्लॉक के ग्राम पनहुर निवासी किसान लच्छू राम यादव के साथ हुई धोखाधड़ी की कहानी यह बताते के लिए काफी है कि जिले में जमीन दलालों और ठगों का सिंडिकेट कितना बेखौफ होकर काम कर रहा है। कम ब्याज पर लोन दिलाने के नाम पर शुरू हुआ यह खेल किसान को पुश्तैनी जमीन छीनने और उसे पूरी तरह कंगाल करने पर जाकर खत्म हुआ।

लोन दिलाने के बहाने मिली ठगों की कड़ी

किसान लच्छू राम यादव अपने ट्रैक्टर की रुकी हुई किरतें चुकाने के लिए बैंक से लोन लेने के सिलसिले में लगातार चक्कर काट रहे थे। इसी दौरान बैंक के बाहर उनकी मुलाकात हर्ष यादव नाम के व्यक्ति से हुई। हर्ष यादव ने कम ब्याज दर पर पैसा दिलवाने का झांसा दिया और किसान का विश्वास जीतकर उनकी जमीन का पट्ट,



आधार कार्ड और पैन कार्ड अपने पास जमा करा लिया। जब कई दिनों तक पैसे नहीं मिले और किसान ने संपर्क किया, तो पता चला कि उनका पूरा दस्तावेज कांकेर के जमीन दलालों तक पहुंच चुका था।

हाफ रजिस्ट्री के नाम पर छलावा, करा ली फूल रजिस्ट्री

कांकेर के जमीन दलाल हेमलाल बघेल ने किसान को जमीन गिरवी रखकर 18 लाख रुपये दिलाने की बात कही। इसके बाद किसान को ‘हाफ रजिस्ट्री’ (बंधक/अल्पकालिक दस्तावेज) कराने का झांसा देकर तहसील ले जाया गया, लेकिन झांसे में रखकर पूरी जमीन की ‘फूल रजिस्ट्री’ करा ली गई। रजिस्ट्री प्रक्रिया पूरी होने के बाद किसान को 18 लाख रुपये (कुछ नकद और

कुछ बैंक खाते के जरिए) सौंप दिए गए। लेकिन असली साजिश का खेल उसी दिन से शुरू हुआ।

18 लाख रुपये की ऐसे हुई सुनिवेशित ‘लूट’

रजिस्ट्री व कमीशन का खेल: हाफरजिस्ट्री का झांसा देने की एवज में किसान से तत्काल 1.25 लाख रुपये ऐंट लिए गए।

इसके तुरंत बाद दलालों ने अपना ‘कमीशन’ बताकर 2 लाख रुपये और वसूल लिए। पैसा डबल करने का हर्बल स्कैम: इसके बाद दलाल हेमलाल बघेल ने किसान को भानुप्रतापपुर तक छोड़ा और झांसा दिया कि एक हर्बल कंपनी में 8 लाख रुपये लगाने पर पैसा डबल हो जाएगा, जिससे वे अपना ट्रैक्टर का कर्ज आसानी से चुका सकेंगे। किसान से 8 लाख रुपये और ऐंट लिए गए। किसान के बैंक खाते में जो बची हुई राशि आई थी, दलालों ने पहले से लिए गए बैंक चेक का इस्तेमाल कर 6.50 लाख रुपये खाते से निकाल लिए। इसके बाद टेमन साहू नामक व्यक्ति ने किसी अन्य काम का बहाना बनाकर 10 हजार रुपये और ले लिए। 18 लाख रुपये में बेची गई जमीन के बदले किसान के हाथ में अंततः महज 15 हजार रुपये बचे।

जमीन भी गई, पैसा भी गया और ट्रैक्टर भी खींच ले गया शोरूम

किसान लच्छू राम यादव ने जिस ट्रैक्टर की किरत पटाने के लिए इस पूरी प्रक्रिया की शुरुआत की थी, किरत न पट पाने के कारण शोरूम वाले उस ट्रैक्टर को भी उखाकर ले गए। आज किसान के पास न उसकी जमीन बची है, न पैसे और न ही ट्रैक्टर। यह घटना दर्शाती है कि जिले में बैंक परिसरों के आसपास दलालों का समानांतर नेटवर्क सक्रिय है, जो जबरूतमद और भोले-भाले ग्रामीणों को चिह्नित कर शिकार बना रहा है।

छत्तीसगढ़ सर्व पिछड़ा वर्ग समाज आया आगे, आंदोलन की चेतावनी

इस भीषण ठगी की खबर मिलते ही ‘छत्तीसगढ़ सर्व पिछड़ा वर्ग समाज’ के प्रतिनिधियों ने पीड़ित किसान लच्छू राम यादव से मुलाकात की और घटना की पूरी जानकारी ली। पिछड़ा वर्ग समाज के नेताओं ने पीड़ित को हर संभव न्याय दिलाने का भरोसा जताया है। पिछड़ा वर्ग समाज ने निर्णय लिया है कि जल्द ही आरोपी दलालों के खिलाफ संबंधित थाने में आपराधिक मामला दर्ज कराया जाएगा। पूरे मामले की लिखित शिकायत जिला कलेक्टर से की जाएगी।

केदार कश्यप के 17 साल के कार्यकाल पर विधायक हम्मला कहा- बस्तर की उपेक्षा के लिए याद किया जाएगा आपका कार्यकाल



बीजापुर। प्रदेश के वन मंत्री केदार कश्यप द्वारा छत्तीसगढ़ में सबसे लंबे समय तक कैबिनेट मंत्री रहने का रिकॉर्ड बनाने पर बीजापुर विधायक विक्रम मंडावी ने बधाई देते हुए तीखा हमला बोला है। विधायक मंडावी ने फेसबुक पर पोस्ट कर पूछा है कि 17 साल 8 महीने मंत्री रहने के बाद भी बस्तर को आपने क्या दिया? विधायक ने पोस्ट में लिखा- केदार कश्यप जी छत्तीसगढ़ में सबसे लंबे समय तक कैबिनेट मंत्री बनने का खिताब आपको मिल रहा है, मेरी तरफ से भी आपको बधाई। चार बार मंत्री पद की शपथ ली, मंत्री के रूप में आदिवासी विभाग, वन विभाग समेत कई महत्वपूर्ण विभाग संभाले, 6,472 दिन (17 वर्ष 8 महीने) का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। अब बस्तर संभाग के आम गाँव गरीब आदिवासी, युवा बेरोजगार, महिला, छोटे व्यापारी, छात्र आपसे जानना चाहते हैं कि बस्तर संभाग को आपने 17 वर्ष 8 महीने में क्या दिया? बस्तर की किस मुड़े को लेकर आपने आवाज उठाई? बस्तर के समस्याओं को लेकर आप हमेशा मौन रहते हैं? नारायणपुर जिले के बदहाल सड़कों का जिम्मेदार कौन है? बस्तर का युवा

विकसित भारत यूथ लीडर डायलॉग 2027 के अंतर्गत विजय

कोण्डागांव। भारत सरकार युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा आयोजित विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग-2027 का आयोजन 10 से 12 जनवरी 2027 तक नई दिल्ली में प्रस्तावित है। उक्त कार्यक्रम के विकसित भारत चैलेंज ट्रैक युवाओं के विचारों एवं नवाचारी मुद्दाओं को विकसित भारत /2047 के लक्ष्य से जोड़ने हेतु प्रमुख मंच है। इसके अंतर्गत प्रथम चरण में विकसित भारत क्रिज का आयोजन 17 अगस्त से 16 सितंबर तक माई भारत पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किया जा रहा है। उक्त क्रिज में 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के युवा पात्र हैं तथा क्रिज में चयनित प्रतिभागी आगामी चरण में निबंध एवं प्रस्तुतीकरण की प्रक्रिया में सम्मिलित होंगे। अतः यह गतिविधि युवाओं को जिला स्तर से राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर तक अपनी प्रतिभा एवं विचार प्रस्तुत करने का महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करेगा।

पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से मिली बड़ी राहत, अब नहीं आता बिजली बिल

दंतेवाड़ा। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जिले के नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही है। योजना के माध्यम से लोग स्वच्छ ऊर्जा अपनाने के साथ-साथ बिजली खर्च में भी



उल्लेखनीय बचत कर रहे हैं। दंतेवाड़ा जिले के बड़े तुमनार निवासी कैलाश कुमार देवांगन इसकी एक प्रेरक मिसाल हैं। कैलाश कुमार देवांगन ने मार्च 2026 में अपने घर की छत पर 3 किलोवाट क्षमता का सोलर फ्लूटफॉप प्लांट स्थापित कराया। वे अपने गांव के पहले हितग्राही हैं जिन्होंने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ लिया। कैलाश देवांगन वर्तमान में ग्रीष्म विकासखंड के ग्राम मोफलनार स्थित माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं। कैलाश बताते हैं कि पहले उनके घर का मासिक बिजली बिल लगभग 1000 से 1200 रुपये तक आता था। हालांकि सोलर पैनल स्थापित होने के बाद से उन्हें बिजली बिल का भुगतान नहीं करना पड़ रहा है। उनके अनुसार घर में चार सदस्य रहते हैं और उनकी आवश्यकताओं के लिए 3 किलोवाट का सोलर संयंत्र पर्याप्त है। पहले घर में लगभग 200 यूनिट बिजली की खपत होती थी, जिसका भुगतान करना पड़ता था, लेकिन अब सौर ऊर्जा के कारण यह खर्च लगभग समाप्त हो गया है। उन्होंने बताया कि मार्च माह में शिक्षकों की एक बैठक के दौरान पीएम सूर्य घर योजना की विस्तृत जानकारी दी गई थी, जिसमें वे भी शामिल हुए थे। योजना के लाभ और संभावनाओं को समझने के बाद उन्होंने अपने घर की जरूरतों के अनुसार सोलर संयंत्र लगाने का निर्णय लिया। इसके सकारात्मक परिणामों का अनुभव कर रहे हैं। देवांगन का कहना है कि सरकार द्वारा योजना के तहत प्रदान की जा रही सब्सिडी इसकी सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक है। इससे आम परिवारों के लिए सोलर संयंत्र स्थापित करना आसान हो गया है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि अधिक से अधिक नागरिक इस योजना का लाभ लें और अपने बिजली खर्च को कम करें। कैलाश कुमार देवांगन का मानना ​​है कि यह योजना केवल आर्थिक रूप से ही लाभदायक नहीं है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनका कहना है कि भविष्य में बिजली की मांग और दरों में वृद्धि होने की संभावना है, ऐसे में सौर ऊर्जा अपनाने वाले परिवारों को इसका विशेष लाभ मिलेगा। स्वच्छ और अस्थाय ऊर्जा का उपयोग आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेगा। जिला प्रशासन एवं विद्युत विभाग ने नागरिकों से पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ उठाने की अपील की है। यह योजना घरों को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के साथ-साथ हरित एवं टिकाऊ विकास की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।



उल्लेखनीय बचत कर रहे हैं। दंतेवाड़ा जिले के बड़े तुमनार निवासी कैलाश कुमार देवांगन इसकी एक प्रेरक मिसाल हैं। कैलाश कुमार देवांगन ने मार्च 2026 में अपने घर की छत पर 3 किलोवाट क्षमता का सोलर फ्लूटफॉप प्लांट स्थापित कराया। वे अपने गांव के पहले हितग्राही हैं जिन्होंने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ लिया। कैलाश देवांगन वर्तमान में ग्रीष्म विकासखंड के ग्राम मोफलनार स्थित माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं। कैलाश बताते हैं कि पहले उनके घर का मासिक बिजली बिल लगभग 1000 से 1200 रुपये तक आता था। हालांकि सोलर पैनल स्थापित होने के बाद से उन्हें बिजली बिल का भुगतान नहीं करना पड़ रहा है। उनके अनुसार घर में चार सदस्य रहते हैं और उनकी आवश्यकताओं के लिए 3 किलोवाट का सोलर संयंत्र पर्याप्त है। पहले घर में लगभग 200 यूनिट बिजली की खपत होती थी, जिसका भुगतान करना पड़ता था, लेकिन अब सौर ऊर्जा के कारण यह खर्च लगभग समाप्त हो गया है। उन्होंने बताया कि मार्च माह में शिक्षकों की एक बैठक के दौरान पीएम सूर्य घर योजना की विस्तृत जानकारी दी गई थी, जिसमें वे भी शामिल हुए थे। योजना के लाभ और संभावनाओं को समझने के बाद उन्होंने अपने घर की जरूरतों के अनुसार सोलर संयंत्र लगाने का निर्णय लिया। इसके सकारात्मक परिणामों का अनुभव कर रहे हैं। देवांगन का कहना है कि सरकार द्वारा योजना के तहत प्रदान की जा रही सब्सिडी इसकी सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक है। इससे आम परिवारों के लिए सोलर संयंत्र स्थापित करना आसान हो गया है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि अधिक से अधिक नागरिक इस योजना का लाभ लें और अपने बिजली खर्च को कम करें। कैलाश कुमार देवांगन का मानना ​​है कि यह योजना केवल आर्थिक रूप से ही लाभदायक नहीं है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनका कहना है कि भविष्य में बिजली की मांग और दरों में वृद्धि होने की संभावना है, ऐसे में सौर ऊर्जा अपनाने वाले परिवारों को इसका विशेष लाभ मिलेगा। स्वच्छ और अस्थाय ऊर्जा का उपयोग आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेगा। जिला प्रशासन एवं विद्युत विभाग ने नागरिकों से पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ उठाने की अपील की है। यह योजना घरों को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के साथ-साथ हरित एवं टिकाऊ विकास की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति आवेदन 30 सितंबर तक

जशपुरनगर। जिले में अध्ययनरत कक्षा पहली से 12वीं तक के दिव्यांग छात्र-छात्राओं के लिए नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के माध्यम से छात्रवृत्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जारी है। पात्र विद्यार्थी 30 सितंबर 2026 तक छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं। छात्रवृत्ति हेतु आवेदन करने के लिए विद्यार्थियों को सबसे पहले नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद अत्याह्न ट स्कॉलरशिप विकल्प में लॉगिन कर आधार का सत्यापन करना होगा। आधार सत्यापन के पश्चात मांगी गई आवश्यक जानकारी दर्ज कर आवेदन पूर्ण करना होगा। आवेदन के लिए मूल निवास प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, नवीनतम आय प्रमाण पत्र तथा पूर्व वर्ष की अंकसूची सहित आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद आवेदन संबंधित विद्यालय की संस्था आईडी में प्रदर्शित होगा। विद्यालय के प्रधान पाठक अथवा प्राचार्य द्वारा आवेदन का सत्यापन कर उसे समाज कल्याण विभाग, जशपुर की आईडी में ओरिजिनल किया जाएगा। इसके पश्चात समाज कल्याण विभाग द्वारा आवेदन को राज्य स्तर पर भेजा जाएगा और भेजा जाएगा तथा विद्यार्थियों को डिबीटी के माध्यम से छात्रवृत्ति की राशि उनके बैंक खाते में प्रदान की जाएगी। छात्रवृत्ति आवेदन प्रक्रिया के लिए संबंधित विद्यालय अथवा शैक्षणिक संस्था का एनसीपी पोर्टल पर पंजीयन होना आवश्यक है।

महापौर ने विकास कार्यों को समय पर पूरा करने का दिया निर्देश, रेवाडीह में किया भूमिपूजन

शहर के रेवाडीह वार्ड में 30 लाख रुपए की लागत से होंगे विकास कार्य

राजनांदगांव. वार्डों में चल रहे निर्माण कार्य निरीक्षण की कड़ी में महापौर मधुसूदन यादव ने लखौली, रेवाडीह में चल रहे निर्माण कार्य का निरीक्षण कर कार्य को समय-सीमा में पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने अग्रवाल ट्रांसपोर्ट के पास कबीर द्वार निर्माण के लिए पार्श्व चंद्रशेखर लश्करे, पूर्व पार्श्व अमीन हद्द तथा समाज के लोगों के साथ स्थल निरीक्षण किए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि कबीर द्वार निर्माण कार्य जल्द प्रारंभ करे, तथा द्वार निर्माणा वाहनों के आवागमन को देखते हुए तथा ड्राईंग डिजाईन के अनुसार हो इसका विशेष ध्यान रखा जाए। महापौर के निर्देश पर अधिकारियों ने तत्काल लेआउट दिए। इसी प्रकार महापौर ने गायत्री स्कूल रोड विश्वकर्मा मंदिर के पास निर्माणाधीन सामुदायिक

अधिकारियों से बोले महापौर...झाड़ंग डिजाइन के हिसाब से ही हो निर्माण कार्य



भवन का निरीक्षण कर कार्य में तेजी लाकर शेष कार्य जल्द पूर्ण करने कहा। उन्होंने कहा कि आगामी दिनों में भवन का लोकार्पण कराया जाना है, जिसके आधार पर भवन का सभी कार्य पूर्ण किया जाए। निरीक्षण के दौरान महापौर श्री यादव रेवाडीह पहुंच रेवाडीह में स्वीकृत विकास कार्यों की जानकारी लिए। निर्माण कार्य के लिए प्रक्रिया पूर्ण होने की जानकारी पर महापौर ने वार्ड

पार्श्व व खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की प्रभारी सदस्य बिना ध्वव, नामांकित पार्श्व सूर्यकांत श्रीवास, पूर्व पार्श्व मुकेश ध्वव तथा वार्डवासियों की उपस्थिति में अघोसंरचना मद अंतर्गत स्वीकृत 19.82 लाख रुपये की लागत से रोड एवं नाली निर्माण तथा 10 लाख रुपये की लागत से गोठन व कर्मा मंदिर के पास शेंड निर्माण के लिए पूजा अर्चना कर विधिवत भूमिपूजन किए।

उन्होंने अधिकारियों से कहा कि निर्माण कार्य अविलंब प्रारंभ करे, और प्रतिदिन मानिट्रिंग करे, जिससे समय सीमा में गुणवत्ता के साथ कार्य पूर्ण हो सके और उसका लाभ वार्डवासियों को मिल सके। इस दौरान उन्होंने आदिवासी समाज के लिए निर्माणाधीन सामुदायिक भवन का निरीक्षण कर समाज की भावना के अनुरूप भवन निर्माण के निर्देश दिए।

हाइवे से लगे गांवों की रजिस्ट्री पर लगा बैन हटाने की मांग, कलेक्टर को ज्ञापन

जिला पंचायत सदस्य अंगेश्वर देशमुख ने कलेक्टर जितेंद्र यादव से की मुलाकात

राजनांदगांव। हाइवे से सटे गांवों में जमीन की रजिस्ट्री पर लगे प्रतिबंध को हटाने की मांग को लेकर जिला पंचायत सदस्य अंगेश्वर देशमुख ने कलेक्टर जितेंद्र यादव से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा है। दो अलग-अलग प्रतिबंधों को लेकर उन्होंने मांग की है कि दोनों की प्रतिबंधों को हटया जाना चाहिए। ताकि जमीनों का पंजीयन कराया जा सके। कलेक्टर को दिए गए ज्ञापन में देशमुख ने कहा कि टेडेरसा, मुडीपार, घूक्का सहित आसपास के गांवों में प्रस्तावित फोरलेन के कारण जमीन की रजिस्ट्री पर बैन लगाया गया था। अब उक्त प्रस्तावित फोरलेन को निरस्त किए जाने की जानकारी सामने आई है। इसके बावजूद संबंधित गांवों में जमीन की रजिस्ट्री पर लगा प्रतिबंध जारी है। वहीं



दूसरे पत्र में रायगढ़ से परमालकसा प्रस्तावित रेल लाइन का हवाला देते हुए रजिस्ट्री पर लगाए गए प्रतिबंध को हटाने की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि सोमनी-टेडेरसा क्षेत्र के आसपास के गांवों में रेल लाइन प्रस्तावित होने के कारण जमीन की रजिस्ट्री पर बैन लगाया गया था। जानकारी के मुताबिक रेल लाइन का सर्वे हो चुका है तथा रेल लाइन में आने वाली जमीन एवं खसरा

का चिन्हांकन भी किया जा चुका है। रेल विभाग द्वारा चिन्हांकित खसरा की सूची उललब्ध कराए जाने का भी उल्लेख पत्र में किया गया है। देशमुख ने कलेक्टर से मांग की है कि जिन गांवों में वर्तमान परिस्थितियों में रजिस्ट्री पर प्रतिबंध की आवश्यकता नहीं है, वहां लगा बैन हटया जाए, ताकि ग्रामीणों और जमीन मालिकों को हो रही परेशानी से राहत मिल सके।

तीज के रंग में रंगा पाटन, साहू समाज की महिलाओं ने दिखाई संस्कृति की समृद्ध छटा'

पाटन में सजा तीज का भव्य दरबार, हजारों सामाजिक जनों की मौजूदगी में गूंजे छत्तीसगढ़ी गीत

पाटन। तहसील साहू संघ पाटन के तत्वावधान में महिला प्रकोष्ठ संयोजिका के नेतृत्व में 6 सितंबर 2026 को तहसील स्तरीय तीज महोत्सव एवं तीज मिलन समारोह 2026 का भव्य आयोजन हर्षोन्नस के साथ किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत भक्त माता कर्मा एवं नंदिया बैल की विधिवत पूजा-अर्चना के साथ हुई। तीज मिलन समारोह में छत्तीसगढ़ महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. ममता साहू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुईं। कार्यक्रम में पूर्व कैबिनेट मंत्री श्रीमती रामशिला साहू एवं जिला साहू संघ अध्यक्ष नंदलाल साहू विशेष रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश साहू संघ महिला संयोजिका दिव्या कलिहारी ने की। विशेष अतिथियों में शिष्या साहू, सह-संयोजिका महिला प्रकोष्ठ प्रदेश साहू संघ, कल्पना नाराद साहू, जिला पंचायत सभापति, चंद्रिका साहू, कार्यकारिणी सदस्य प्रदेश साहू संघ, मंजू साहू, उपाध्यक्ष जिला साहू संघ, ललेश्वरी साहू, महिला संयोजिका जिला साहू संघ तथा दामिनी राकेश साहू, जनपद सदस्य पाटन शामिल रहें।

महिलाओं की सहभागिता ने कार्यक्रम को बनाया भव्य

स्वागत भाषण तहसील साहू संघ पाटन के अध्यक्ष लालेश्वर साहू ने दिया। उन्होंने तीज मिलन समारोह में समाज के महिला-पुरुषों की बड़ी संख्या में सहभागिता पर सभी को बधाई दी। उन्होंने कहा कि पांचों परिक्षेत्र सहित 99 इकाइयों की महिला पदाधिकारियों एवं सामाजिक बहनों के विशेष सहयोग से कार्यक्रम सफल हुआ। तीज महोत्सव में महिलाओं के लिए विभिन्न आकर्षक कार्यक्रम आयोजित किए गए। छत्तीसगढ़ी पारंपरिक खेल, गीत-संगीत, पारंपरिक व्यंजनों की बर्गिया तथा भक्त माता कर्मा की चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की गई। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया।साथ ही पारंपरिक वशभूषा प्रतियोगिता में तीज क्रीन के रूप में प्रथम स्थान तेलीगुंडरा परिक्षेत्र से विभा साहू और द्वितीय स्थान पर ली बेल्हारी परिक्षेत्र से ज्योति साहू साथ ही अन्य तीन तीज क्रीन को भी सम्मानित किया किया। लालेश्वर साहू ने कहा कि तीज महोत्सव केवल उत्सव नहीं, बल्कि हमारी छत्तीसगढ़ी संस्कृति, परंपरा और सामाजिक एकता को मजबूत करने का अवसर है। ऐसे आयोजनों से



समाज की महिलाओं को अपनी प्रतिभा और संस्कृति को प्रदर्शित करने का मंच मिलता है।

सामाजिक कुरीतियों से हटकर शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक मजबूती पर दें जोर : डॉ. ममता साहू

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. ममता साहू ने कहा कि समाज में सहभागिता हम सभी की जिम्मेदारी है। यदि समाज को संस्कारवान और मजबूत बनाना है तो प्रत्येक व्यक्ति को समाज से जुड़कर अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी और अपने भविष्य का निर्धारण करना होगा। उन्होंने कहा कि साहू समाज को केवल रोटी-बेटी के संबंधों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि रूढ़िवादी परंपराओं से हटकर आधुनिक सोच के साथ आगे बढ़ना होगा। शादी-विवाह, मृत्यु संस्कार एवं जन्मोत्सव जैसे आयोजनों में अनावश्यक खर्च को कम करने की आवश्यकता है। उन्होंने विवाह समारोहों में साड़ी जैसे उपहारों के आदान-प्रदान की परंपरा को कम करने की अपील करते हुए कहा कि यह सोचने के बजाय कि हमें उपहार मिला है तो हमें भी देना है, समाज को खर्च कम करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने सामाजिक आदर्श विवाह को प्रोत्साहित करते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक मजबूती को समाज की प्राथमिकता बनाने का आह्वान किया। कार्यक्रम को पूर्व कैबिनेट मंत्री रामशिला साहू, महिला संयोजिका दिव्या कलिहारी, सह संयोजिका शिष्या साहू और जिला पंचायत सभापति कल्पना नाराद साहू ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम मे संरक्षक अश्वनी भूनेश्वरी साहू, महासचिव महेंद्र साहू, कोषाध्यक्ष गुमान साहू, महिला संयोजिका कोमिन साहू,अशोक साहू, रामनारायण साहू, गायत्री साहू, पारखत साहू, किशन हिरवानी, छत्रपाल साहू, रवि शंकर साहू, छान साहू, सुखदेव साहू, गंगा दीन साहू, नाराद साहू, डोमन साहू ,कामता साहू, सरजू राम साहू, गरीबदास ,डीजेन्द्र साहू , पून लाल, कल्याण साहू, योगेश साहू , दीलीप साहू, सुमन साहू, अमृत साहू, शैलेन्द्र साहू, जागेत्री साहू,रता साहू, द्रोपती साहू, देव कुमार साहू, जोगीराम साहू, रामनाराय साहू, बीरेन्द्र साहू, राजू साहू, भुवन साहू, बंटी साहू, तोरन, मीडिया प्रभारी करन साहू साहू सहित हजारों की संख्या मे समाज के लोग उपस्थित रहे। संजू साहू के द्वारा छत्तीसगढी सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम का संचालन खेमलता साहू ने किया। तीज मिलन समारोह में महिलाओं की उत्साहपूर्ण सहभागिता और पारंपरिक रंग ने पूरे आयोजन को यादगार बना दिया।

दोषमुक्त प्रकरणों की आईजी यादव ने की समीक्षा, 11 विवेचकों को शो-कॉज नोटिस जारी

नोटिस का जवाब मिलने के बाद जरूरत पड़ी तो विभागीय जांच भी कराएंगे

राजनांदगांव। जिले के 395 प्रकरणों की समीक्षा मंगलवार को आईजी अजय यादव ने की। ये वह प्रकरण हैं, जिसमें आरोपी दोषमुक्त हो गए। पूरे प्रकरणों की समीक्षा में यह सार सामने आया कि 11 प्रकरणों में विवेचकों ने त्रुटियां की और 28 प्रकरण अपील योग्य हैं। इस समीक्षा के बाद आईजी यादव ने 11 विवेचकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सर्वोच्च न्यायालय के क्रिमिनल अपील गुजरात राज्य विरुद्ध किशन भाई में पारित आदेश के परिप्रेक्ष्य में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप वर्ष 2026 के मई के 208 और जून के 187 कुल 395 दोषमुक्त प्रकरणों की विवेचना व अभियोजन कार्यवाही में हुई त्रुटियों की समीक्षा की गई!

रेंज के सभी जिलों के अधिकारी समीक्षा बैठक में हुए शामिल



समीक्षा के दौरान बैठक के दौरान 11 प्रकरण विवेचक त्रुटि और 28 अपील योग्य प्रकरण पाया गया। समीक्षा के दौरान पुलिस महानिरीक्षक यादव द्वारा आपराधिक प्रकरणों की प्रभावी एवं गुणवत्तापूर्ण विवेचना, अभियोजन से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं तथा प्रकरणों के न्यायालय में सफलतापूर्वक निराकरण ds f4,

आवश्यक कार्रवाई पर विस्तृत चर्चा की गई। साथ ही संबंधित अभियोजन अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि न्यायालय लंबित प्रकरणों में प्रभावी पैरवी करते हुए दोषसिद्धि में बढोत्तरी करने पर जोर दिया गया। बैठक में प्रभारी संयुक्त संचालक-उपसंचालक अभियोजन रेंज डी.के जैन, उपसंचालक अभियोजन जिला

कबीरधाम कुलरंजन कुजूर, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी खैरागढ़ सुनील कुमार राठौर, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी अंबागढ़ चौकी ललित साहू तथा पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गीता वाघवानी, उप पुलिस अधीक्षक नवी मोनिका पांडे उपस्थित रही।

पुलिस अफसरों ने गणेश समितियों की ली मीटिंग, सीसीटीवी, फायर सेफ्टी को लेकर दिए निर्देश

गणेश पर्व को लेकर पुलिस विभाग भी तैयारी में जुटा, 70 से अधिक समितियां आई बैठक में

महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों एवं दिव्यांग श्रद्धालुओं की सुरक्षा एवं सुविधा का विशेष ध्यान रखने कहा

राजनांदगांव। आने वाले सप्ताह से गणेश पर्व शुरू हो जाएगा। इसे लेकर पुलिस विभाग ने भी होमवर्क शुरू कर दिया है। इसी क्रम में मंगलवार को पुलिस विभाग के आला अफसरों ने शहर की 70से अधिक गणेश समितियों के साथ मीटिंग की। इसमें पंडालों में सीसीटीवी कैमरा, पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था, सुरक्षित विद्युत वायरिंग एवं अग्नि सुरक्षा को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए। साथ ही महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों एवं दिव्यांग श्रद्धालुओं की सुरक्षा एवं सुविधा का विशेष ध्यान रखने तथा पर्याप्त संख्या में पहचान योग्य स्वयंसेवकों की व्यवस्था करने के लिए समितियों को कहा गया।



बैठक में गणेश उत्सव के दौरान शांति, सुरक्षा एवं सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के साथ-साथ बेहतर समन्वय एवं भीड़ प्रबंधन को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा ने सभी समितियों से अपील की कि उत्सव को धार्मिक आस्था एवं उत्साह के साथ

अनुशासन और जिम्मेदारी के साथ मनाया जाए। किसी भी प्रकार की अप्रवाह, विवाद अथवा असामाजिक गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को देने तथा कानून-व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करने के लिए समितियों को समझाइश दी गई।

देखरेख के अभाव में बटंग धान खरीदी केंद्र की व्यवस्था बदहाल, खुले में पड़ी भूसी बारिश में हो रही खराब

समय-सीमा की बैठक

मुंगेली। जिले में आम नागरिकों की समस्याओं के त्वरित निराकरण और शासन की योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक समयबद्ध रूप से पहुंचाने के उद्देश्य से प्रशासन द्वारा निरंतर मानिट्रिंग की जा रही है। इसी क्रम में कलेक्टर अमृत विकास तोपनो ने जिला कलेक्टरेट सभाकक्ष में आयोजित समय-सीमा बैठक में विभिन्न विभागों के कार्यों, योजनाओं और लंबित प्रकरणों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को आम नागरिकों से जुड़े मामलों को प्राथमिकता के साथ लेते हुए निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में 17 सितंबर से प्रस्तावित सेवा संकल्प अभियान के शुभारंभ की तैयारियों की भी समीक्षा की गई। आगामी धान खरीदी को लेकर कलेक्टर ने जिले के उपार्जन केंद्रों की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने बादाना उपलब्धता, भंडारण व्यवस्था, किसानों के पंजीयन तथा उपार्जन केंद्रों में आवश्यक मूलभूत सुविधाओं की जानकारी लेते हुए सभी व्यवस्थाएं समय रहते पूर्ण करने के निर्देश दिए।

पाटन। पाटन ब्लॉक अंतर्गत सेवा सहकारी समिति मर्यादित बटंग के धान खरीदी केंद्र में इन दिनों अव्यवस्था का आलम देखने को मिल रहा है। देखरेख के अभाव में धान खरीदी केंद्र का घेरा क्षतिग्रस्त होकर जालीतार टूट गया है। वहीं धान खरीदी पूर्ण होने के बाद बड़ी मात्रा में भूसी को सुरक्षित रखने के बजाय खुले में छोड़ दिया गया है, जिसके चलते बारिश के पानी से भूसी खराब हो रही है।

बताया जा रहा है कि भूसी को सुरक्षित रखने के संबंध में विभागीय अधिकारियों द्वारा पहले ही निर्देश दिए जा चुके हैं, इसके बावजूद धान खरीदी केंद्र में खुले में पड़ी भूसी की सुरक्षा और रखरखाव को लेकर जिम्मेदारों द्वारा कोई गंभीर पहल नहीं की जा रही है। बारिश के कारण भूसी लगातार खराब हो रही है। वहीं टूटा हुआ जालीतार होने के कारण मवेशी भी धान खरीदी केंद्र के अंदर प्रवेश कर खुले में पड़ी भूसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस अव्यवस्था को लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। लोगों का कहना है कि



किसानों और समिति के हित से जुड़े संसाधनों का इस तरह लापरवाही से रखरखाव किया जाना आर्थिक नुकसान का कारण बन सकता है। आने वाले दिनों में राज्य सरकार द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के तहत धान खरीदी की तैयारी शुरू की जाएगी। ऐसे में यदि पहले से खरीदी गई भूसी का उचित रखरखाव नहीं किया गया और वह बारिश में खराब होती रही, तो समिति को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है।

स्थानीय लोगों ने मांग की है कि धान खरीदी केंद्र में क्षतिग्रस्त जालीतार की तत्काल मरम्मत कराई जाए तथा खुले में पड़ी भूसी को सुरक्षित स्थान पर रखा जाए, ताकि बारिश और मवेशियों से होने वाले नुकसान को रोका जा सके। साथ ही पूरे मामले की जांच कर लापरवाही के लिए जिम्मेदार लोगों पर आवश्यक कार्रवाई की जाए। फिलहाल मामले में जिम्मेदार अधिकारियों की चुप्पी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं।

अल्ट्राटेक कुकुरदी सीएसआर द्वारा संचालित सिलाई प्रशिक्षण कार्यक्रम की मुख्य परीक्षा संपन्न

बलौदाबाजार। अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड, कुकुरदी सीमेंट वर्क्स द्वारा निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत ग्राम ढनढनी एवं सरकीपार में संचालित 3 माह के बेसिक सिलाई प्रशिक्षण कार्यक्रम की मुख्य परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न हुई। ढनढनी केंद्र में परीक्षा का आयोजन आज किया गया, जबकि सरकीपार केंद्र में मुख्य परीक्षा पूर्व में 4/9/26 आयोजित की जा चुकी है। उल्लेखनीय है कि यह प्रशिक्षण कार्यक्रम 1 मई से 31 जुलाई तक संचालित किया गया, जिसके लिए दोनों ग्रामों में स्थानीय सिलाई प्रशिक्षिकाओं की नियुक्ति की गई थी। प्रशिक्षण का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं एवं बालिकाओं को रोजगारोपमुखी कौशल प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर एवं आर्थिक रूप से सशक्त बनाना था। मुख्य परीक्षा में दोनों केंद्रों की कुल 60 प्रशिक्षणार्थी महिलाओं एवं बालिकाओं ने सहभागिता की। परीक्षा के दौरान प्रतिभागियों के सिलाई संबंधी



तकनीकी ज्ञान, माप लेने की क्षमता, डिजाइनिंग की समझ, परिमाण निर्माण कौशल तथा प्रशिक्षण अवधि में अर्जित दक्षताओं का मूल्यांकन लिखित एवं प्रायोगिक परीक्षा के माध्यम से किया गया। प्रशिक्षणार्थियों ने पूरे उत्साह और आत्मविश्वास के साथ परीक्षा में भाग लेते हुए अपने कौशल का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। इस प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र आगामी सप्ताह में दिये जाने की योजना है। अल्ट्राटेक कुकुरदी के सीएसआर प्रमुख राजेन्द्र कुशवाहा ने बताया कि प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से महिलाओं एवं बालिकाओं के स्वरोजगार के अवसरों से जोड़ने तथा उनकी आय बढ़ाने की दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

प्रशिक्षण पूर्ण होने के उपरांत प्रतिभागी सिलाई एवं परिधान निर्माण कार्य के माध्यम से स्वयं का रोजगार स्थापित कर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकेंगी। कार्यक्रम के दौरान प्रशिक्षणार्थियों ने अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड, कुकुरदी सीमेंट वर्क्स के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस प्रकार के कौशल विकास कार्यक्रमों से उन्हें नई आजीविका के अवसर प्राप्त हुए हैं तथा उनके आत्मविश्वास में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यह पहल महिला सशक्तिकरण, कौशल विकास, स्वरोजगार संवर्धन एवं सतत आजीविका निर्माण की दिशा में अल्ट्राटेक ककरदी के प्रतिबद्ध प्रयासों का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं एवं बालिकाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के साथ-साथ उन्हें स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।